हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च 1979

(द्वितीय बैठक)

खण्ड 1 अंक 14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 22 मार्च 1979

पृश्ठ संख्या

वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा (पुरारम्भ)	(14) 1
अध्यक्ष द्वारा घोशणा– सदन के स्थगित होने के संबंध में दैनिक हिन्दी 'वीर प्रताप' में एक समाचार छपने संबंधी	(14) 22
वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	(14) 28
वाक आउट	(14) 40

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 22 मार्च 1979

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 15.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबार 1979–80 के बजट पर अब बहस फिर जारी रहेगी। सुबह सदन में जो मैम्बर स्पीच दे रहे थे, वे अपनी स्पीच जारी रखें।

श्री फतेह चन्द विज(पानीपत): स्पीकर साहब, कुछ साहेबान ने बोलते हुए जाने अनजाने में या जान बूझ कर भाहर और देहात की डिवैल्पमैंट का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार स्टेट की भलाई के लिये कोई अच्छे काम नहीं कर रही है हालांकि बजट के आंकड़ों से स्पश्ट है कि कितनी डिवैल्पमैंट के काम हो रहे हैं। कुछ मैम्बर जो अपने आपको मिनी जनता पार्टी के सदस्य बताते हैं चौधरी गंगा राम जी इसके लीडर हैं। जब वे बोल रहे होते हैं तो उनकी बात का भाहर के साथ कोई संबंध

नहीं होता। वे कोई बात भाहर की डिवैल्पमैंट के लिये नहीं कहेंगे। भाहर के नाम को तो उनको फोबिया हो गया है। वे कहते हैं कि मेरा घर गोहान में है लेकिन अगर गोहाने का रहने वाला कोई व्यक्ति कोई काम के लिये कहे तो वे कहते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको वोट दिया है उसको कहो। एक लैजिस्लेटर के लिये, चाहे वह अपोजी ान पार्टी से ताल्लुक रखता है, चाहे ट्रैजरी बैंचिज से ताल्लुक रखता है, अगर वह चुन कर असैम्बली में आ गया है तो उसके लिये यह बात भाोभा नहीं देती। मैम्बर बनने के बाद यह लफ्ज अगर वह कहें तो कोई अच्छी बात नहीं है। स्पीकर साहब, बजट के आंकड़े देखने से मालूम होता है जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने कहा कि बजट का 75 परसैंट पैसा देहातों पर खर्च हा रहा है। आपके सामने बजट पड़ा है, आप इसको देख कर बता दें कि सरकार ने भाहरों की डिवैल्पमैंट के लिये कितना पैसा अलाट किया है। हालांकि भाहर प्रदे ा की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन कहीं पर भी भाहर की डिवैल्पमैंट का जिक्र नहीं है। मैं पानीपत कांटीच्युऐंसी से ताल्लुक रखता हूं यह एक ओद्योगिक नगर है और 50 करोड़ रुपये के करीब का औद्योगिम माल तैयार होता है। यह माल सारे भारतवर्श में तो जाता ही है, दे ा विदे ा में भी ऐक्सपोर्ट होता है और लाखों रुपया फौरन ऐक्सचेंज के रूप में कमा कर देता है। फौरन के ट्रेडर जब पानीपत भाहर में माल खरीदने के लिये आते हैं तो भाहर में घुसते ही नाक पर कपड़ा रख लेते हैं और कहते हैं कि बड़ी बदबू है, हम भाहर के

अंदर नहीं जा सकते। इस प्रकार कई भाहर ऐसे हैं जो करोड़ों रुपये का फौरन ऐक्सचेंज कमाकर देते हैं लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है। मेरे अपोजी ान के भाई बैठे हैं 32 लाख रुपया एक पार्क की डिवैल्पमैंट के लिये यूथ कांग्रेस को दिया था जिसके नेता चौधरी सुरेन्द्र सिंह थे। ये यूथ कांग्रेस के नाम पर रुपया ले गये और थोड़ा सा रुपया पार्क पर खर्च करके बाकी रुपया खुद खा गए ..... इतना रुपया उसकी डिवैलपमैंट पर लगा ही नहीं लेकिन 32 लाख रुपया पार्क की डिवैल्पमैंट के नाम पर डाल दिया गया। (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः किसी मैम्बर के बारे में यह कहना कि ..... ये लफ्ज ठीक नहीं हैं, इनको एक्सपेंज किया जाए। This is a very vauge allegaiton and it should be expunged. There can be not end to such allegations.

श्री अध्यक्षः किसी मैम्बर पर बाई नेम एलीगे ान लगाना ठीक नहीं है।

श्री फतेह चन्द विजः मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। 32 लाख रुपया यूथ कांग्रेस के नाम पर ले गये और 32 लाख में लाखों रुपया डैकोरे ान पर लगा दिया, जब संजय गांधी करनाल में आये थे। लोगों की खून पसीने की कमाई को वहां लगा दिया जहां पर संजय गांधी जाया करते थे, वहां की सजावट पर खर्च कर दिया और ..... स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि टैक्स पेयर्ज का पैसा जहां पर खर्च किया जाना

चाहिए था, वहां खर्च न करके किसी दूसरी जगह पर खर्च किया जाए तो आप उसको क्या कहेंगे। हमारे फाइनैंस मिनिस्टर बाबू मूल चन्द जैन ने ऐसे हालात में बजट तैयार किया जब प्राकृतिक प्रकोप सारी स्टेट में छाया हुआ है। जब जनता सरकार बनी तो बाढ़ की मुसीबत आई, हरियाणा की धरती का दो तिहाई हिस्सा पानी में डूब गया। सरकार ने फौरन रिलीफ के कार्य भ्ारू कर दिए और अपोजि ान वाले मैम्बरों का आहवान दिया कि तुम भी सहायता कार्य में सहयोग करो। ये नहीं ओय और बंगलों में सोते रहे। अपने अपने हलके में भी नहीं गए, किसी काम में हिस्सा नहीं लिया और कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें जनता की भलाई हो और आज यहां सदन में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं जनता पर आपत्ति आने पर अपनी कोठियों से नहीं निकले। इनका फर्ज बनता था कि लोगों की मदद करते। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर पर टोकरियां उठा उठा कर भलाई का कार्य किया, आप उनकी फोटो देख सकते हैं (व्यवधान) अपोजी ान के मैम्बरों ने पीड़ित जनता के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई लेकिन जनता सरकार ने इस मुसीबत का तहदिल से, दिलेरी के साथ मुकाबला किया। राव साहब उस वक्त दुआ मांग रहे थे कि हरयाणा बरबाद हो (व्यवधान) अभी लोगों को बसाये जाने का काम पूरा भी नहीं हुआ था कि ओले पड़ गये। स्पीकर साहब, कांग्रेस पार्टी ने 30 साल राज किया, लेकिन कभी किसान को ओले पड़ने पर पर्याप्त सहायता नहीं दी। ये जो कांग्रेसी बने बैठे हैं और जनता सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं, अगर इनके जमाने में इतने ओले पड़

जाते थे तो रिलीफ देने के लिये दो तीन महीने के बाद लोगों को खाद, बीज, पानी देते थे। जो रिलीफ दिया लेकिन हमारे सी0एम0 साहब ने ओलें पड़ते ही एलान किया कि पीड़ित लोगों को 100 रुपया, 200 रुपया और 300 रुपया फी किल्ले के हिसाब से ग्रांट दी जाए। इस प्रकार 8 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई। इतेन कठिन हालात में से गुजरने के बावजूद भी इन्होंने एलान करने में देर नहीं की। मेरे अपोजी ान के भाइयों को इस काम की सराहना करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई।

स्पीकर साहब, हमारे वित्त मंत्री जी ने घाटा पूरा करने के लिये टैक्सिज की प्रपोजल रखी है। मैं इनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि हलवाइयों के ऊपर टैक्स न लगाए। अगर लगाना है तो इनकी दो तीन कैटेगरी बना कर 50 या 100 रुपया लाइसैंस फीस लगा दी जाये। सरकार ने आमदनी का जो अंदाजा लगाया है वह लाइसैंस के रूप में पूरा किया जाए। हलवाई का बहुत छोटा धंधा है। इन छोटे आदमियों के लिए हिसाब किताब लिखना मु कल है। अगर ये हिसाब किताब रखने की कोि ा ा करेंगे तो गलत रास्ते अख्तियार करेंगे कुरप ान बढ़ेगी। इसलिए उनको टैक्स से छूट देनी चाहिए।

स्पीकर साहब, मैं सूत की मिल्ज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मैं पानीपत से ताल्लुक रखता हूं, वहां पर सूत की बड़ी मिलें हैं। सरकार ने सूत मिलों पर एक परसैंट से 2 परसैंट टैक्स बढ़ाने का नि चय किया है। स्पीकर साहब, एक परसैंट टैक्स से

9 लाख रुपये की आमदनी सरकार को होती थी। सरकार सोचती है कि 2 परसैंट बढ़ाने से अधिक आमदनी होगी, ऐसी बात नहीं है। सूत मिलों ने हरियाणा में अपने डिपो खोल रखे हैं। टैक्स बढ़ाने से वे अपने डिपू दिल्ली में खोल देंगे ताकि उनको सैल्ज टैक्स कम देना पड़े। इस तरह सारा टैक्स दिल्ली वाले ले जाएंगे। हरियाणा को कोई फायदा नहीं होगा। पिछले साल दो तीन जगहों पर डिपू खोल दिए हैं जिनसे 9 लाख रुपये का सैल्ज टैक्स आया। अगर उन पर टैक्स बढ़ायेंगे तो वे अपने डिपो दिल्ली में ले जाएंगे और जो 9 लाख रुपया सरकार को आमदनी होती थी, वह भी जाती रहेगी, आपकी जेब से निकल जाएगी, इस बात को आप सोच लें।

स्पीकर साहब, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मेरा भी ख्याल है और हमारे साथियों का भी यही ख्याल है कि हमारी सरकार अगर भाराब के ठेकों को नीलाम करती तो यह घटाा नहीं होता। लाटरी सिस्टम लागू करने से सरकार को घाटा हुआ है। हमारी सरकारने जो टैक्स लगाये हैं, इनके लगाने की आव यकता नहीं थी। अब जो ठेके नीलाम हो रहे हैं, दस दस गुना अधिक कीमत पर नीलाम हो रहे हैं इन ठेकों से सरकार को 10—12 करोड़ रुपये की आमदनी हो जायेगी जो कि पिछले साल नहीं हो पाई थी।

श्री अध्यक्षः आपको कोई नया सुझाव देना चाहिए। यह तो पहले ही आ चुका है।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए रिक्वैस्ट करूंगा कि जहां पर सरकार 90 परसैंट पैसा गांव पर खर्च करने जा रही है वहां पर कुछ भाहरों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी तायल साहब ने कहा कि सभी कमेटियों के आंकड़े मंगवा लें, जिस म्युनिसिपल कमेटी को जितने पेसे की आव यकता हो उसके अनुसार डिवैल्पमैंट के लिये पैसे दे दिए जायें। कई कमेटियौं की डिवैलपमैंट तो तीन तीन और चार चार साल से रूकी हुई है। कांग्रेस सरकार ने 1977 से पहले भाहरों को खूबसूरत बनाने के नाम से पैसा खर्च किया है वह वहां पर पूरा खर्च नहीं हुआं। उसमे से ज्यादातर पैसा बरबाद हुआ है। इसलिये मेरी गुजारि ा है कि सभी कमेटियों की आव यकता के बारे में पता करके उनकी सहायता की जाये और पैसे की ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यू ान की जाए।

स्पीकर साहब, मैं आखिर में राव साहब को कहना चाहता हूं कि वे बड़े पुराने और लायक सदस्य हैं। वे अपोजी ान के लीडर भी बन बैठे हैं उनकों यहां हाउस में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि अब जो ओले पड़े हैं यह और पड़ेगे और सन् 1982 तक बिल्कुल बरबाद हो जायेंगे। यह भाोभाजनक बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह(तो ाम): स्पीकर साहब, कई दिनों से सन 1979–80 के बजट पर बहस चल रही है और काफी माननीय

सदस्यों ने अपने विचार हाउस में प्रकट किये हैं। मेरे से पहले वक्ताओं ने कुछ सुझाव भी सदन में रखे हैं।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान बोलने वाले बहुत हैं। अगर हाउस की सैंस हो तो हर मैमबर पर टाईम की लिमिट लगा दी जाये ताकि दस मिनट से अधिक कोई भी सदस्य न ले। अभी वित्त मंत्री जी ने भी बोलना है। उन्होंने भी घंटा सवा घंटा लेना है। इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि कोई भी सदस्य दस मिनट से ज्यादा न ले।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आज जो गांव और भाहर की बात की जाती है यह बिलकुल गलत है। मैं विज साहब से दरखास्त करूंगा कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। असल बात देखने की यह है कि जनता सरकार ने देहातों के लिए क्या कुछ किया और भाहर वालों के लिये क्या कुछ नहीं किया। डाक्टर साहब ने भी काफी चर्चा की कि कांग्रेस ने यह किया वह किया। नुक्ताचीनी करने का उनका हक है लेकिन हैल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं चौधरी देवी लाल जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वे देहात के लिये कुछ कर नहीं पाये हैं लेकिन कम से कम नारा तो उन्होंनें दिया। उन्होंने यह नारा तो लगाया कि किसानों के लिए यह होना चाहिए और कुछ कदम भी उठाये हैं। उन्होंने न केवल देहात के लिए उठाये बल्कि भाहर वालों के लिये भी उठाये। यह कहना भूल है कि भाहर वालों के लिए कुद नहीं किया और गांवों के लिये सब

कुछ कर रहे हैं भाहरों के लिए भी बराबर किया जा रहा है। यहां पर मैचिंग ग्रांट की भी बात कही गई। अगर देहात में कोई धर्म ाला के निर्माण के लिये पैसा दिया जाता है तो भाहरों में भी दिया जाता है जैसे अब काम करने के बदले में पैसों की जगह अनाज दिया जायेगा तो भाहरों और देहातों में दोनों जगहों पर दिया जायेगा चाहे कोई पानीपम में है या भिवानी में है सब को बराबर मिलेगा।

स्पीकर साहब, जनता सरकार ने फैसला किया है कि चालीस मील का एरिया जो दिल्ली के नजदीक है वहां सब्जी बोने का प्रोग्राम बताया है क्योंकि वहां के लोग दिल्ली की मार्किट से फायदा उठा सकेंगे। मैं इस बात का स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अगर इस बजट को अच्छी तरह से पढ़ा जाये तो ज्यादा टेक्स किसानों पर ही लगे हैं। विज साहब इस बात को कहना ही भूल गये कि उन भी टैक्स ज्यादा लगे हैं। अगर किराया बढ़ा है तो किसानों पर , देहात के लोगों पर बढ़ा है। देहात के लोगों को रोजाना भाहर में आना पड़ता है चाहे वे अपने मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए आयें या अपने परिवार के लिए कपड़ा, नमक या अन्य चीजें खरीदने के लिए आयें। जब वह भाहर में आयेगा तो उस पर भी भार पड़ेगा। यह साढ़े बारह परसैंट का अधिक भार किसानों पर पड़ेगा।

इसके अलावा हलवाईयों पर टैक्स बढ़ा है जिसकी सेल चालीस हजार से ज्यादा होगी उसको सैल्ज टैक्स देना पड़ेगा। यह भी देहात के लोगों पर ही पड़ेगा। गांव के लोग जब भाहरों में आयेंगे तो मिठाई जरूर खायेंगे। उनके पास चाहे पांच रुपये हों या दस रुपये हों लेकिन वे अपनी मिठाचई के पैसे जेब में अलग से रख लेते हैं। चाहे लड्डू खायें या जलेबी खायें, मिठाई अव य खायेंगे। इसलिए मिठाई पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

स्पीकर साहब, सरकार ने स्टाम्प डयूटी भी बढ़ाई है। यह बहुत गलत बात की है, बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए थी। इसी तरह से किसानों पर सवा तैंतीस परसैंट लैंड टैक्स बढ़ाया है। कुछ भाई इस बात को समझे नहीं हैं कि सबसे ज्यादा बोझा किसान पर पड़ा है। छोटा किसान ही मार्किट में जाता है उसको ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। जितना रैविन्यू किसान से आता है उतना और किसी तबके से नहीं आता है। आज हरियाणा में छोटे किसान की दुर्द ा हो रही है। यहां पर जो यह कहते हैं कि समाज कल्याणकारी राज्य है। अगर समाज कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं तो इन छोटे किसानों पर से यह टैक्स वापिस लेना चाहिए। बड़े कारखानेदारों पर यह टैक्स लगना चाहिए।

डाक्टर साहब ने सदन में बताया कि कांग्रेस सरकार के वक्त बिग हाउसिज को सबसिडी दी जाती थी। उन्होंने जिन्दल हाउसिज का भी जिक्र किया।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): मैंने जिन्दल हाउसिज का नाम नहीं लिया।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैं तो जनता सरकार के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बजट में कोई योजना रखी है कि बिग हाउसिज की सबसिडी खत्म करेंगे। हरियाणा के बजट में कोई ऐसी बात नहीं आई और न ही सैंटर के बजट में ऐसी कोई बात आई है। आज अपने दिल पर हाथ रख कर बतायें कि क्या बिड़ला फैक्टरीज और दूसरे लोगों को जो यह नौ नौ लाख की सबसिडी दी जाती है यह बन्द की जाएगी ?

डाक्टर मंगल सैनः फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि बिग हाउसिज की सबसिडी बंद करने जा रहे हैं लेकिन इस बात को सच तो तभी माना जायेगा जब यह प्रैक्टिकल रूप सें लागू हो जाएगी।

स्पीकर साहब, सरकारने जो टैक्स लगाए हैं उनको खत्क करने के बारे में कुछ सुझाव भी सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। भाहरो ंमें जिसका प्लाट, दुकान या कोई इम मूवेबल प्रोपर्टी है, उसकी आज कीमत बढ़ चुकी है। जिस भाई ने यह पहले दस हजार में खरीदी थी आज भाहर की डिवैल्पमैंट होने से उसकी कीमत बढ़ चुकी है। वह दस हजाचर की जमीन अगर दो लाख में या चार लाख में बिके तो उस पर ट्रांसफर डयूटी ज्यादा रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो चल सम्पत्ति है और

स्टाक करने की वजइ से अगर उसकी कीमत बढ़ गई है और वह चल सम्पत्ति बाजार में बिकती है तो उस पर सेल्ज टैक्स या कोई ओर टैक्स बढ़ाना चाहिए। सरकार लग्जरी गुडज पर भी टैक्स लगा सकती है जैसे एयर कंडी ानर हैं या दूसरे ऐ ाो आराम की चीजें हैं। सरकार खर्चों में कमी की जा सकती है। स्पीकर साहब, ये लोग पहले कांग्रेस सरकार की नुक्ताचीनी करते थे और जब पब्लिक में जाते थे तो कहते थे कि हम सादगी से रहेंगे। एयर कंडी ानर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम बड़ी कोठियों में नहीं रहेंगे लेकिन आज ये उन बातों को भूल गए हैं। स्पीकर साहब, इसके अलावा यह कहा जाता था कि ि ाक्षा प्रणाली के अंदर हम रैडीकल चेंज लायेंगे। चुनाव प्रणाली को बदलेंगे और यह नारा भी दिया था कि राइट टू रिकाल को मानेंगे और इसको अमली जामा पहनायेंगे। ये राइट टू रिकाल को मान लेते थे अच्छा हो जाता क्योंकि उस वक्त जो हवा आई थी उसका फैसला हो जातां यह जो नई भर्ती आई थी वह सारा फैसला हो जाता अगर ये लोग राइट टू रिकाल को मान लेते ....

चौधरी लाल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब नई भर्ती में तो ये भी भाामिल हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इसके अलावा इन्होंने लोकल बौड़ीज के चुनाव का नारा दिया था। इन्होंने कहा था कि जीतने के बाद हम हर स्तर पर इलैक ान करवायेंगे। यह मैं

मानता हूं कि इन्हौंने पंचायतों के चुनाव करवाए हैं लेकिन जिला परिशदों को दुबारा चालू नहीं किया। म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव दो बार पोस्टपोन हो चुके हैं। (व्यवधान) जिला परिशद के एक्ट में अमैंडमैंट करके दुबारा लागू नहीं किया गया (व्यवधान) ययानी आप इस बात को मानते हैं कि जिन्होंनें म्यूनिसिपल कमेटीज को तोड़ा था उन्होंने ठीक तोड़ा था। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से एक दरखास्त है कि पिछले साल एम0डी0 यूनिवर्सिटी में किसान के बच्चों के लिए बीस या पच्चीस सीट रिजर्व की थीं लेकिन लोगों ने उस आड्डर को चेलेंज करके हाईकोर्ट से सैट असाइड करा लिया था, चाहे किसी कानून की भाक्ल में या किसी आर्डिनैंस के जरिए किसान के बच्चों के लिये उतनी ही सीटें जरूर रिजर्व करें जिससे कि देहात के बच्चों को उसमें दाखिला मिल सके।

स्पोटर्स के लिए काफी पैसा रखा गया है लेकिन ज्यादा पैसा राई स्कूल के लिए खर्च किया जा रहा है। मुझे खु ी है कि हरियाणा के दो पहलवान ए ियन गेम्ज में जीत कर आए थे उनको सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया है। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि कपिल देव, जिन्होंनें हरियाणा का नाम सारे संसार में ऊंचा किया है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कमिटमैंट नहीं आई है। इसके अलावा मैं एस0वाई0एल0 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सरकार की बहुत ज्यादा इच्छा है कि कैरियर चैनल को जल्दी से जल्दी बनवाया

जाए। मैं पोलिटिकल बात नहीं करता लेकिन सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सभी पार्टीज को कौंफिडैंस में लेकर पौलिटिक्स से ऊपर होकर फैसला करें। पंजाब वाले कभी दफा 480 का नोटिस दे देते हैं, कभी कुछ और अड़चन डाल देते हैं और अगर कभी इस चीज का फैसला भी हो गया तो बाद में सैंकड़ों रिटस पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट में करवा देंगे। मेरा सुझाव है कि आप पंजाब की बसें हरियाणा की सड़को से दूसरी जगह जाती हैं उनमे बारे में सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब, कैरियर चैनल हरियाणा के किसान की रीढ़ की हड्डी है। स्पीकर साहब, 35 लाख एकड़ जमीन के लिये जो पानी पिछली सरकार ने लिया था आप उसको ठीक नहीं मानते और आप उसको बढ़वा भी नहीं सके। यह सरकार तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो एवार्ड दिया था उसको भी इम्पलीमैंट नहीं करवा सकी (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सुझाव भी दिया जाता है उसको भी यह सरकार नहीं मानती है ....

श्री अध्यक्षः चौधरी सुरेन्द्र सिंह, अब आप वाइंड अप करें।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही कहना है कि स्पोर्टस के लिये यूनिवर्सिटी के लिये जौ पैसा दिया जा रहा है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हों

आज सब जगह चर्चा है कि पीने का पानी दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब जब मेरी कांस्टीच्यूऐंसी में गए तो

इन्होंने कहा कि इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि जो पांच गैलन की स्कीम है उसको दस या पंद्र गैलन में तबदील कर दिया जाए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरी कांस्टीच्युऐंसी है वह बहुम बैकवर्ड है। वहां पर पानी की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, इरीगे ान की दिक्कत है, स्कूलों की दिक्कत है। इन सब दिक्कतों को ध्यान में रखकर मेरी कांस्टीच्युऐंसी के लिये कुछ किया जाए।

श्री हरफूल सिंह(फतेहाबाद): स्पीकर साहब, जो बजट पे ा किया गया है इसमें किसानों और गरीबों के लिए बहुत गुंजाइ ा है। इसमें सड़कों की बात कही गई है। ज्यादा बसें बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें पानी के लिए जोर दिया गया है चाहे वह पानी नहर की भाक्ल में है और चाहे वह टयूबवैल की भाक्ल में है पानी के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है ताकि दे ा के अंदर पैदावार बढ़ सके। हरिजनों के लिए बहुत कुछ सोच विचार हो रहा है। हर गांव में चौपाल बनाई जा रही हैं उद्योग धंधों में हरिजनों को बराकर का हिस्सा दिया जा रहा है। इस नीति के अधीन यह किया गया है कि एक हरिजन एक गैर हरिजन और एक तीसरा आदमी मिलकर अगर कोई उद्योग चलायेंगे तो सरकार उनकी सहायता करेगी। इससे बेरोजगारी दूर होगी।

विज साहब ने भाहर की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि भाहर कोई अलग नहीं है। भाहर देहात से जुड़े हुए हैं। भाहर

और देहात में कोई फर्क नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी यह जो बजट है इसमें ज्यादा इ ारा देहातों को उठाने की तरफ है क्योंकि देहात काफी पीछे चले गये हैं स्पीकर साहब, आज देहात में रहने वालों की हालत चाहे वह हरिजन हैं, खेतीहर मजदूर हैं या दूसरे मजदूर हैं उनके पैरों में जूते नहीं हैं उनके पास मकान नहीं है उनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, और स्पीकर साहब, जब सर्दियां होती हैं तो बगल में हाथ डालकर अपने दिन काटते हैं। कांग्रेस सरकार तो इनती निकम्मी थी कि उसने देहात को ऊपर उठाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे तो मगरमच्छ थे।

स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि बाड़ को बिल्कुल खत्क कर दिया जाएगा। पिछले तीस साल में यह होता रहा है कि दो दो, तीन तीन करोड़ रुपया बाढ़ की रोकथाम के लिए खर्च किए जाते थे। लेकिन होता यह था कि पानी को रोकने के लिये थोड़ी सी मिट्टी गिरा दी जाती थी और अगले साल जब फल्ड आते थे तो वह मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। इस प्रकार से कांग्रेस सरकार पैसा खर्च करती रहती थी।

स्पीकर साहब, अब मैं करप ान की बात कहना चाहता हूं, पुलिस की भी बात कता हूं। आपको यह पता होगा कि करप ान तब चलती थी, जबकि राज्य में करप ान करवाई जाती थी, चन्दा लोगो ंसे जबरी तौर पर इकट्ठा किया जाता था। उस चंदे की हद मुकर्रर की जाती थी, मौके पर डी0सी0, एस0डी0ओ0,

एस0पी0 और दुसरे बड़े बड़े अफसर लोगों से जबरी तौर पर पैसा इकट्ठा करवाते थे और यह कहते थे कि तेरा फलां काम तब होगा जबकि तू इतने पैसे चंदे के रूप में सरकार को देगा और 6–6 लाख और 8–8 लाख रुपयाच मालाओं के रूप में लिया जाता था, इस प्रकार से ये लोग ब्लैक मेल करते थे यह थी करप ान जो कि पिछली सरकार के वक्त में होती थी। (प्र ांसा) पिछले तीस सालों में यही कुछ होता रहा है और आज ये लोग यहां पर कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारी इस जनता सरकार ने तो एक साल में किसानों के लिए सब कुछ कर दिखाया है जो कि इनकी सरकार तीस सालों में नहीं कर सकी। (प्र ांसा) सड़कों की बात, हस्पतालों की बात, नहरों की बात, स्कूलों की बात और भी कई सराहनीय काम हमारी सरकार ने इस थोड़े से अर्से में कर दिखाये हैं जो कि कांग्रेस सरकार 30 सालों में भी नहीं कर पाई थी। इनको तो केवल एक ही रट लगी रहती थी कि नौकरी, नौकरी, नौकरी। स्पीकर साहब, ये लोग कोई धंधा कर सकते हैं ओर आजय इन्होंने हमें इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारी सरकार को बड़े कठोर परिश्रम से आगे बढ़ना पड़ रहा है। यह सब कुछ हमारे माननीय चौधरी देवी लाल जी की मेहरबानी है जो कि इतने थोड़े अर्से में बेकारी को दूर कर भगाया है नहीं तो इन्हौंनें तो हमें बेकार ही करके बिठा दिया था।

स्पीकर साहब, ये लोग यहां पर दुहाई देते हैं कि हमारी सरकार किसानों के लियें, गरीबों के लिये कुछ नहीं कर रही है, यह बिल्कुल गलत है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो सवा छः एकड़ पर टैक्स माफ किया है इसको बहुत फायदा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी हमारे गरीब किसान भाईयों को कुछ न कुछ तो फायदा है ही। उन भाईयों को यह तो अब उम्मीद हो गई है कि कम से कम हमारे रखवाले भी यहां पर बैठे हैं जो कि हमारे हकों के लिये लड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हरफूल जी अब आप समाप्त कीजिएं

श्री हरफूल सिंहः बस जी, मैं एक दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। स्पीकर साहब, मैं अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से और अपने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह अपील करूंगा कि जमीन के ऊपर जो टेक्स लगाया है और जो दूसरा कोई किसी किस्म का टैक्स जो कि गरीब आदमियों किसानों पर , हरिजनों पर पड़ता हो, उसको वापिस ले लिया जाए तो मुझे बड़ी खु ी होगीं मुझे नजर आ रहा है कि मेरे इस प्वायंट पर मेरे माननीय मुख्य मंत्री महोदय बड़े खु ा दिखाई दे रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इस टैक्स को वापिस ले लेंगे क्योंकि किसानों पर अभी पड़ने वाले ओलों का बड़ा असर पड़ा है। स्पीकर साहब, आप को यह पता होगा कि अभी पिछले दिनों ओले पड़ गये जिसके कारण किसान की फसल को बड़ा नुक्सान हुआ

है। अभी अभी मुझे बताया गया है कि चनों को भी इन आलों के कारण काफी नुकसान हुआ है तो मेरी अपनी सरकार से अपील है कि कम से कम आप उन भाइयों पर ही रहम खाएं और जो टैक्स जमीन पर, आबियाना वगगरह लगाया गया है, उसकी माफी दे दी जाए। मेरा विचार है कि जैन साहब तो मेरे से सहमत हैं और मुझे पूर्ण आ ा है कि मुख्य मंत्री महोदय भी मेरे इस विचार से सहमत होकर किसानों पर रहम खायेंगे। इन भाब्दों के साथ मैं समाप्त करता हुआ अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री कंवल सिंह (घिराये): स्पीकर साहब, यहां इस सदन में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच पढ़ी और उसमें सरकार के किये हुए कामो ंपर रो ानी डाली गई और आगे जो काम सरकार करने जा रही है, उस के बारे में भी जिक्र किया। हमारी सरकार ने इस प्रान्त के अंदर प्रान्त की तरक्की के लिये कुछ योजनाएं बनाई है और आगे उन्होंने जिक्र किया है कि इन योजनाओं को सरकार को सिरे लगाने के लिये पैसे की आव यकता है और इस आव यकता को पूरा करने के लिए इस बजट स्पीच में कुछ टैक्सिज की प्रोपोजल भी की गई है और जब वह प्रोपोजल यहां पर रखी गई तो हमारे कुछ साथियों ने उस पर एतराज भी किया। स्पीकर साहब, वैसे तो मैं समझता हूं कि ये बातें पार्टी मीटिंग में करनी चाहिए, लेकिन फिर भी स्पीकर साहब, हम उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उस वर्ग को रिप्रैजैंट करते हैं,

जिसके ऊपर पिछले 30 सालों से बड़े जुल्म किये जाते रहे हैं। स्पीकर साहब, ये कांग्रेसी भाई क्या बोल सकते हैं, मैं बताता हूं कि 1976–77 में इनके समय में घटर कर 10 करोड़ रह गया। इससे आगे मैं बताता हूं कि जो अरबन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स जो 1975–76 में 1.14 था और 1976–77 में 1.47 था जो कि अब बढ़ कर 2.62 हो जाता। यदि हटाया न जाता। (विघ्न) ये कह रहे हैं कि एमरजैंसी की उपलब्धियां हमारे ही काल में हुई। इसके बाद स्टेट भोयर आफ यूनियन एक्साइज डयूटीज को 14 करोड़ की जगह 1966–67 में साढ़े नौ करोड़ वसूल किया। इस प्रकार स्पीकर साहब, ये जाते जाते प्रोफे ानल टैक्स भी अपनी पापुलैरिटी को बढ़ाने के लिये हटा गये और फिर ये कहते हें कि हम तो गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। इन चीजों से सभी वाकिफ हैं, ज्यादा कहने की आव यकता नहीं। अगर देहात को बढ़ावा दिया है तो हमारी सरकार ने ही दिया है। हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री जी की हिम्मत का नतीजा है कि आज लोग गांवों में बड़े प्रसन्न हैं। मुख्य मंत्री महोदय जब भी कहीं जाते हैं तो वे देहात में ही रूकते हैं और भाइयों के बीच में साधारण तरीके से रहते हैं और कई दफा तो अगर मुख्य मंत्री महोदय का प्रोग्राम न भी हो तो भी वे टेढे मेढे रास्तों से होते हुए लोगों के पास पहुंचते हैं और उनके दुख सुख को बड़ी सहन ाीलता से सुनते हैं। स्पीकर साहब, अब मैं उन टैक्सिज का जिक्र करना चाहता हूं जिन टैक्सिज से मुझे एतराज है। हमें इसलिये एतराज है कि ये टैक्स डायरैक्ट टैंक्स हैं जैसे इंकम टैक्स है और जिन की इंकम फिक्सड

है, वे यह टैक्स इवेड नहीं कर सकते लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट हैं, व्यापारी हैं जिनके पास बेहद ब्लैक मनी है, वे टैक्स इवेड करते हैं और जिनके पास एक एक हजार रुपये के नोटों के साथ करोड़ों रुपया जमा पड़ा हुआ था जो खत्म किया गया है उसके बाद और भी रुपया जो ब्लैक मनी के रूप में चल रहा है उन लोगों से इस टैक्स की रिकवरी पूरी नहीं की गई और एमरजैंसी का डंडा केवल गरीबों के सिरों पर चलाया गया और ऐसे बड़े बड़े आदमियों को हाथ तक नहीं लगाया गया।

स्पीकर साहब, पार्लियामैंट के इलैक ान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के एजेन्ट थे उनका सुबेरे सबसे पहला काम यहा होता था कि वे एक हजार के नोटों को बैंक से कै ा करवा के लाते थे और इलैक ानों में वह नोट खर्च किये जाते थे। इस तरह से स्पीकर साहब, गरीबों पर टैक्स लगा कर इलैक ानों पर खर्च किया जाता था। अब इस बजट में जो टैक्स लगाये गये हैं, हमने भी इसका एतराज किया था। स्पीकर साहब, हमारे एतराज के बाद पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें पार्टी के एम0एल0एज0 की एक कमेटी बनाई गई जिसका काम यह था कि वह यह सुजैस्ट करे कि कौन सा टैक्स लगाना है और कौन सा हटाना है। उस कमेटी ने अपने सुझाव दे दिये हैं और मुझे उम्मीद है कि मुख्य मंत्री महोदय तथा वित्त मंत्री महोदय जी हामरी रिकमैंडे ांज पर पूरा ध्यान देंगे। एक बात मेरे को याद आ गई कि किसी आर्टिस्ट ने किसी भाहर के बार एक फोटा लगाई। उसने लोगों

को कहा कि बताओं इसमें क्या क्या कमी हैं ? तो लोगों में से किसी ने उस तसवीर की टांग इधर की खींच दी और किसी ने नाक को इधर को कर दिया। यानी सारी तसवीर को खराब कर दिया। दूसरे दिन उसी आर्टिस्ट ने कहा कि तसवीर का यह खाका है इसको देखकर तसवीर बनाओ तो सब चुप रह गये। तो हम तो उस आर्टिस्ट की तरह हैं जिसने ठीक तसवीर बनाई थी। हमने जैन साहब को बहुत अच्छी तसवीर बना कर दी है और अगर उसे वे अपना लें तो हरियाणा का कल्याण हो जाएगा। हमने कुछ टैक्स हटा कर दूसरे टैक्स लगाने की रिकमैंडे ांज दी थी। जैसे अब इन्होंने सवा छः एकड़ से ऊपर वाले किसान पर टैक्स लगाया है तो उस हिसाब से मैं इनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप यह हिसाब लगा लें कि जिसके पास बीस एकड़ जमीन है उसकी आमदनी कितनी बैठती है और उतनी ही आमदनी वाले सभी वर्गों पर टैक्स लगा दें। केवल किसान को ही रगड़ा न लगाया जाये। किसान तो सब का भला सोचला है वह जब बिजाई भुरू करता है तो कहता है कि भगवानी कीड़ी को भी दियो, कुत्ते को भी दियो। पिछली सरकार ने छोटे बड़े का नारा देकर किसान को डिवाइडिड रखा। यह पिछली गवर्नमैंअ की पालिसी रही है और मैं अपनी गवर्नमैंट से उम्मीद करता हूं कि वह इसी पालिसी पर नहीं चलेगी। चीफ मिनिस्टर साहब भी गांवों में जाते हैं और जैन साहब भी रूरल एरिए को रिप्रजैन्ट करते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि वे किसानों को अच्छी तरह से समझते हैं। यह वर्ग बराबर युनाइटिड नहीं है। इसलिए लोग इसका नाजायज फायदा उठा

लेते हैं। युनिटी की बात मैं बताता हूं कि यूनिटी हमारे में भी नहीं है। मंत्रियो में लंबी गाड़ियों के लिये या इम्पोर्टिड गाड़ियों के लिये झगड़ा रहता है। पता नही लंबी गाड़ियों में क्या है ? हम हिन्दु स्तान में गांधी जी का और जे0पी0 का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो गांधी जी और जे0पी0 कोई नहीं पूछता।

श्री अध्यक्षः अब आपका समय हो चुका है, आप वाइंड अप करें।

श्री कंवल सिंहः मैं वाइंड अप करते वक्त यही कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार जाते जाते कुछ टैक्स हटा गई थी। उनमें से एक टैक्स आयरन और स्टील का टैक्स भी था जिससे हमें 70 लाख रुपये की आमदनी होने वाली थी उसकी वजह से आज हमें ऐ करोड़ रु0 का घाटा हो रहा है। स्पीकर साहब, एक तो आयरन और स्टील वाला टैक्स रहना चाहिए, एक प्रोफै ान टैक्स रहना चाहिए था और इसी तरह से अर्बन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स भी रहना चाहिए। अगर ये टैक्स लगाये जायें और इनके बावजूद भी अगर आपको पैसा चाहिए तो हम दिल खोल कर देंगे। लेकिर अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम बर्दा ात नहीं करेंगे कि हमारे किसाने के ऊपर डायरैक्टस टैक्स लगाये जायें। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, बजट पर जो चर्चा हुई उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हर सदस्य की यह इच्छा है कि गरीब लोगों पर और किसानों पर चाहे वे भाहर में रहते हैं या देहात में उन पर ज्यादा खर्चा किया जाये या उन पर कर का बोझा कर करके बड़े वर्ग पर कर लगाये जाएं। इस वक्त तो सब सदस्यों की यही इच्छा है लेकिन वोटिंग के वक्त इनकी क्या इच्छा होगी यह मैं कह नहीं सकता। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है जैसे न्याय के बार में अंग्रेजी की एक फ्रेज है – "Justice should not be done but it should appear to have been done" तो स्पीकर साहब, यही बात अगर दूसरे तरीके से मैं कहूं तो किसान की, गरीब देहाती की भलाई सिर्फ दिखनी नहीं चाहिए बल्कि वह सही मायनों में करने की बात होनी चाहिए। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** डिप्टी स्पीकर साहब, अगर बजट पर नजर डाल कर देखी जाये तो ऐसा महसएूस होता है कि सारे बजट का 45 प्रति ात से लेकर 48 प्रति ात तक का भाग सिफ उन खर्चों पर जाता है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की तनखाह आ जाती है, दफतरों को मेनटेन करने का खर्च और अफसरों की तनखाहें। तो यह बात बिलकुल साफ है और सदन में भी यह बात आई कि इसका निर्णय केन्द्र के फाइनैंस मिनिस्टर महोदय चौधरी चरण सिंह ने लिया है कि एक केन्द्री कमि ान आन एक्सपैंडिचर बनाया जाएगा। हरियाणा की जनता टैक्स की भाक्ल में 6 सौ करोड़ रुपया भारत सरकार और हरियाणा को देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा का हर व्यक्ति हर रोज के

हिसाब से दो रुपये टैक्स अदा करता है। इससे इस सरकार से यह उम्मी रखी जा सकती है कि यह सरकार लोगों को किस किस्म की राहत देगीं उपाध्यक्ष महोदय, अगर टैक्सों के विवरण को देखा जाए तो जो दस करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाये गये हैं उनमें से आठ करोड़ रुपये के टैक्स तो सीधे किसान पर ही लगाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने तथा तायल साहब ने जो कि बड़े पुरानी पार्लियामैंटेरियन हैं प्रैस वालों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री को इंकम के सोर्स बता सकता हूं अगर उनको ध्यान में रखा जोय तो गरीब लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। जो सरकार समाज कल्याण के लिये बनी हो तथा गरीबों की भलाई के लिये बनी हो, उसका सबसे पहला काम यह है कि वह गरीबो की ि ाक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिये जो चीजें होती हैं वह मुहैया करें। हरियाणा के अंदपर ही ऐसे अनेक डीलर्ज हैं प्रोफै ान करने वाले हैं जिनको लाखों रुपये की कमाई है लेकिन वे कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं और न किसी किस्म का कोई कर अदा करते हैं। हरियाणा के अंदर ऐसे सैंकड़ासें स्कूल हैं जो पब्लिक स्कूलों के नाम से चलते हैं और जिनमें एक एक बच्चे की फीस 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक ली जाती है। उन स्कूलों पर किसी किस्म का कर नहीं लगाया जाता है। मैं यह एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। आप इन चीजों पर नजर डाल कर देखिए कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर लाखों करोड़ों रुपयों का घपला होता है,

लाखों करोड़ों रुपयों की चौरी होती है। जो इस प्रकार की चोरी करते हैं उनको पकड़ा जाये और उन पर टैक्स लगाये जायें। वित्त मंत्री जी ने चार टैक्स किसानों पर लगाये हैं, इन टैक्सों के लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार ने 171 करोड़ रुपया एग्रीकल्चार पर, बिजली प0र और पानी पर खर्च करने का प्लान बनाया है लेकिन मेरा कहना यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी किसान को हरियाणा सरकार से एक पैसे का भी लाभ नहीं होगा, सिर्फ यह बात कह देने से कि टोटल बजट का 75 प्रति ात देहात के किसानों पर खर्च कर रहे हैं। यह उनको धोखे में रखने वाली बात है। आज जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें से 45 प्रति ात तो किसान इस्तेमाल करता है और बाकी 55 प्रति ात कमर्ि यल तबका, व्यापार तबका, और घरों में प्रयोग होता है। ये कहते हैं कि बिजली बोर्ड पर 44 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जायेगी तो यह कैसे हो सकता है कि बजट का 75 प्रति ात पैसा देहात में खर्च होगा ? यह बजट टोटली किसान के खिलाफ है।

दूसरी बात मैं एस0वाई0एल0 के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे प्रान्त के सिंचाई मंत्री जी मेरे ही नाम रार्ि ा हैं, यहां बैठे हें मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं .....

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): मैं आपना नाम रार्ि ा नहीं हूं क्यों आपका नाम 'बी' से भुरू होता है मेरा

नाम 'वी' से भुरू होता है। वी वाले तो मिनिस्टर बन गये और बी वाले मैम्बर ही रह गयें

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि थी डैम में हरियाणा का भी हिस्सा है। लेकिन सरकार से यह भी नहीं होता कि वे अपने हिस्से के लिए चैलेंज कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले जम्मू क मीर के मुख्य मंत्री भोख अब्दुल्ला नें अपने ससदन में यह बात कही कि हिस्सा तो बनता है लेकिन क्यौंकि यह थीं बांध जम्मू क मीर का है इसलिए अगर सदन चाहता है तो मैं इस ऐग्रीमैंट से विदड्रा कर सकता हूं। उनकी आप फारसाईटिडनैंस देखिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हरियाणा सरकार ने पंजाब में नहर बनाने के लिए 7.5 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया है .....

श्री वीरेन्द्र सिहः 7.5 करोड़ का नही, 16 करोड़ का किया है। क्या अपने इसको पढ़ा नहीं ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः क्या इस प्रावीजन से स्टेट में पानी आयेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सिर्फ इसलिये कह रहा था कि 16 करोड़ रुपये मेरे करैक्ट किये हैं उनसे एस0वाई0एल0 की जो नहर बननी है क्या उससे हरियाणा को पानी पहुंचेगा ? पंजाब के लिये जो पैसा रखा है, उसको एक साल से ऊपर हो गया लेकिन वह ऐसे ही पड़ा है। अभी तक पंजाब ने एक इंच भूमि भी इक्वायर नहीं की है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक

हरियाणा सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी तब तक पंजाब एक पैसा भी लगाने को सहमत नहीं होगा। आज इससे हरियाणा की जनता को सौ करोड़ रुपये का हर साल घाटा हो रहा है। दो साल हो गये इस हिसाब से दो सौ करोड़ रुपये का घाटा किसानों को हुआ है। आगे आने वाले समय में भी जब तक आप कोई ठोस कमद नहीं उठायेंगे तो यह नहर नहीं बनेगी। यह जो एस0वाई0एल0 बनाने के लिये पैसा रखा गया है, वह पैसाव बेकार डमप कर दिया गया है। आज आप देखिये नाप्था झाकड़ी प्रोजैकट में हरियाणा का हिस्सा है अगर यह पैसा यहां खर्च किया जाये तो हरियाणा को 50 साल तक बिजली की कमी नहीं हो सकती। जो थर्मल प्लांटस हैं उनको एमरजैंसी परपजिज के लिये ही इस्तेमाल किया जाये क्योंकि वे बहुत महंगे है।

इन बातों के अलावा मैं एक और बात कह कर खत्म करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा में यह हालत हो रही है कि हरियाणा रोडवेज के कैथल डिपो में जनरल मैनेजर की जगह डी0एस0पी0 को नियुक्त किया गया है जैसे हमारे देहात में कहते हें कि रामचंद्र जी सीता से कह गए कि ऐसा कलियुग आयेग, हंस चुकेगा दाना कौआ मोती खायेगा। जब जनरल मैनेजर की जगह डी0एस0पी0 को बैठा दिया। क्या आई0ए0एस0 या आई0पी0एस0 अफसर फैक्टरी चला सकता है ? सरकारने जो 34 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये हैं ये गरीब जनता पर बोझ हैं। मेरे कई साथी कारपोरे ांज के चेयरमैन साहब, लगे हैं उन

कारपोरे ांज के सैंकड़ों डायरैक्टर हैं और अफसर हैं जो उन्हें मनमाने तरीके से चलाते हैं। जनता के अंदर संतोश की भावना लाने के लिये चाहे वह एक एम0एल0ए0 हो या कोई और हो उसे ऐसा होना चाहिए जो सही मायनों में जनता की सेवा कर सकता है। जो इस विद्या में पूरे हैं, इस व्यापार में पूरे हैं उनको ही क्यों ने इन कारपोरें ांज में लिया जाये।

इन बातों के अलावा मैं एक्साई डिपार्टमैंट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा टैक्स का ढांचा ऐसा है कि इसमें किसी भी छोटे तबके को लाभ नहीं पहुंचतां मैं एक बात बताता हूं कि एक 10–12 साल का बच्चा जो किसी की जेब से 50 रुपये का नोट निकाल लेता है उसके खिलाफ कोर्ट में मुकद्दमा चलाया जाता है जिसमें उसे एक साल या छः महीने की सजा होती है परन्तु सैल्ज टैक्स लेने की एक्साईज डिपार्टमैंट की टैक्से ान की पालिसी ऐसी है कि जो लाखों और करोड़ों रुपये के टैक्स की चोरी करता है, लूट करता है, घपला करता है और समाज पर अत्याचार करता है उसको कोई सजा नहीं दी जाती है। उसके लिये दस कानून रखे जाते हैं। यह कहां का न्याय है कि 10–12 साल का लड़का जो सिर्फ 50 रुपये की चोरी करता है उसको तो एक साल की सजा दी जाये और टैक्स चोरी करने वाले को कोई सजा न हो ? आपके हक में यह ठीक नहीं है। आप जनता से वोट लेकर उसको गुमराह कर रहे हैं। अगर आप इसी ढांचे के सहारे चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो

स्वयं को जनता के प्रतिनिधि कहते हैं, यहां बैठे हैं उन पर जनता वि वास करना छोड़ देगी, जनता प्रजातंत्र में वि वास नहीं करेगी। जो टैक्स की चोरी करता है वह इकोनोमिक ओफैण्डर है, उसको कड़ी सजा देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि सरकार ने ऐग्रीकल्चर के लिये इस बजट में करोडों रुपये का प्रोवीजन किया है जो कि खेतीबाडी के लिये खर्च किया जाएगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, यह अच्छे बीज देना और अच्छी खाद देना तो ठीक है लेकिन हरियाणा के गांवों में बसने वाले 40 परसैंट ऐसे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर हैं और उन्होंनें सरकार से कर्जा लेकर के वह ट्रैक्टर लिए हुए है। वह ट्रैक्अर 67 हजार रुपये का आता है इसमें 27 हजार रुपये एक्साइज डयूटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्साइज डयूट न लगाई जाए तो वह ट्रैक्टर 40 हजार रुपये का आ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री जी से यह सुझाव है कि वह चौधरी चरण सिंह जी जो कि हमारे केन्द्रीय वित मंत्री हैं उनसे बातचीत करके कह सकते हें कि किसी भी मकान के लिए ट्रैक्टर की कीमत 30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

16.00 बजे।

चौधरी हुक्म सिंह (दादरी): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो 1979–80 का बजट पे ा किया है इसके बारे में मैं

आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। जब 1947 में दे ा आजाद हुआ तो आजादी के बाद इस दे ा के 80 फीसदी गांवों में रहने वाले किसान और गरीब मजदूर यह सोचते थे कि अब हमारा कोई सुधार होगा और हमें राहत मिलेगी गरीबों को रहने के लिए मकान मिलेंगे बीमारी के अन्दर दवाई का प्रबन्ध होगा और खाने कें लिए पानी का प्रबंध किया, न ही उनके लिए अच्छे बीज और खाद का प्रबन्ध किया और न ही उनको कोई अन्य सहूलियतें दी गई। आज ये कांग्रेसी भाई किसान के हित की बात करते हैं लेकिन इन्होने अपने भाासन काल में हिन्दू कोड बिल पास करके जमीन के टुकडे किए। अमेरीका से अनाज मंगवाने के प चात भी किसानों और गरीबों का पेट अच्छी तरह से नहीं भर सके। ये भाई किसानों के ऊपर जुल्म करते थे और यही चाहते थे कि दे ा के अंदर किसानों का सुधार न हो लेकिन आज ये किसानों की बात करते हैं। जनता पार्टी आने के बाद दो साल के राज में ही अनाज की इनती पैदावार बढ़ गईग है कि यह दे ा सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ बल्कि अनाज दूसरे दे ाों को भेज सकता है। कांग्रेस वाले भाई आज तो देहात की बात करते हैं लेकिन पहले ये देहात में बसने वाले गरीब आदमियों को इंसान नहीं समझते थे। कांग्रैस के भाासन काल में गांवों में रहने वाले हर आदमी को 250 ग्राम चीनी मिलती थी जबकि भाहरों में रहने वाले को 400 ग्राम चीनी मिलती थी लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इस बीमारी को बिलकुल ही खत्क कर दिया है। अब चीनी मार्किट में खुली मिल रही है। यह बात मेरी समझ में नहीं

आती कि कांग्रेस भाासन ने किसानों पर तो लैंड सीलिंग लगा दी कि 18 एकड़ से ज्यादा कोई भी किसान अपने पास जमीन नहीं रख सकता है लेकिन जिनके पास भाहरों में करोड़ों रुपये के मकान हैं या करोडों रुपये की अन्य सम्पत्ति है उन पर कोई सीलिंग नहीं लगाई थी। आज इनको किसानों का बहुत फिक्र हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जिन किसानों के पास 18 एकड से ज्यादा जमीन है उन पर जो 33¼ परसैंट टैक्स का प्रस्ताव है इसके लिए मैं अपने वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस टैक्स को वापिस ले लें। आप भी अपने इलाके में देखते होंगे कि जिस किसान के पास 18 एकड जमीन है उसकी आज क्या हालत है ? उपाध्यक्ष महोदय, राव साहब ने कहा कि जनता सरकार आने के बाद हरियाणा में फ्लड आए लेकिन कांग्रेस सरकार के भाासन काल में लगातार 4–5 साल तक कहत पडते थे। आज जनता पाट्री की सरकार ने पानी का इतना ज्यादा प्रंबंध किया है कि अनाज की पैदावार इतनी बढ़ गई है कि किसानों के पास अनाज रखने के लिए जगह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राम में फ्लड तो कहां आते, उस समय तो बारि ा भी नहीं होती थी। लाखों लोग कहत में मर जाते थे और कितने ही लोग घर छोड कर हरियाणा से बाहर चले जाते थे और आज यह फलड की बात करते हैं अगर फल्ड कहीं आ गया तो हमारे लीडर चोधरी देवी लाल जी ने किसानों के लिए अनाज का, दवाईयों का प्रबंध किया जमीन बोने के लिए ट्रैक्टरों का प्रबंध किया और उनके रहने का इंतजाम किया लेकिन कांग्रेस के भाासन में तो

भगवान भी इतना नाराज था कि कभी इन बातों की जरूरत ही नहीं पडती थीं क्योंकि बारि ा ही नहीं होती थी और अनाज लेने के लिए अमेरिका के पास भागे जाते थे, हमें अनाज दो वरना हमारा दे ा भूखा मर जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान की फसल का मंण्डियों में भाव इतना गिर जाता है कि उनको कीमत पूरी नहीं मिलती। किसान की फसल की आमदनी और ही लागे ले लेते हैं और किसानों के पास कुछ नहीं बचता। इसलिये मेरा सुझाव है कि उसकी जमीन के मुताबिक यह लिमिट हो कि वह अपना अनाज बैंक में रख दे और अपने अनाज के बदले में 60–65 परसैंट रुपया ले लें। जब अनाज का भाव अच्छा आए तो वह अपना अनाज मंडी में बेच करके वह पैसा वापिस बैंक को दे दे। आज जब फसल मंडी में आती है तो अनाज को मंडी में रखने के लिए जगह नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा सुझाव है कि खरीद के सैंटर बना दिए जायें ताकि किसानो ंको अनाज बचेने के लिये मंडी में ज्यादा समय तक रूकना पड़ें ऐसा करने से किसान का अनाज भी खराब नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टैक्स की बात है, यह बहुत अच्छी बात है। टैक्स तो लगने ही चाहिएं।

टैक्सों के बिना किसी दे ा का और प्रान्त का विकास कैसे हो सकता है। यदि सरकार के पास आमदनी नहीं होगी तो

वह प्रान्त का विकास कैसे कर सकती है ? जिस आदमी की टैक्स देने की हैसियत हो, उनसे टैक्स लिये जाऐं। आज जिस किसान के पास 18 एकड जमीन है उसकी कीमत 10 हजार रुपये प्रति एकड के हिसाब से एक लाख 80 हजार रुपये बनती हैं अगर उस पर कुछ टैक्स लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जाहं तक आबियाने की बात है, कांग्रेस सरकार में करीब 50 परसैंट लगान बढ़ाया था लेकिन आज यह किसान के हित की बात करते हैं। दुनियामें कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जिस तरह से गरीब किसानों पर इन्होंने लगान बढ़ा दिया था दूसरे टैक्सों के बारे में भी यही हालत थी। कभी इन्होंने एक परसैंट बढा दिया और कभी दो परसैंट बना दिया।

श्री उपाध्यक्षः अब आप वाइंड अप किजिए।

चौधरी हुक्म सिंहः अच्छा जी। जहां तक लगान की बात है उसको जैन साहब भी समझते हैं क्योंकि वे भी देहात से चुनाव लड कर आये हैं। आपको भी ज्ञात है कि अगर नहर का पानी टूट जाए तो किसान को आबियाना देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हलके मैं सीपेंज की वजह से नहर के आसपास हजारों एकड जमीन में पानी खडा रहात है उसका भी किसान आबियाना देता है इसलिये मेरी वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इसको भी वापिस ले लें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्षः आपका समय हो गया है।

चौधरी हुकम सिंहः सिर्फ एक मिनट लूंगा। थोड़ा सा ि ाक्षा पद्धति के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आजकल जो स्कूलों में ि ाक्षा दी जा रही है। इसको कोई फायदा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता कोई दस्तकारी की ट्रेनिंग स्कूल की पढ़ाई के साथ दी जाने चाहिए। हर स्कूल मे साथ आई0टी0आई0 की क्लासिज का इंतजाम होना चाहिए ताकि पढ़े लिखे बच्चे स्कूल से निकलने के बादप अपना काम धंध कर सकें। कम से कम एक पीरियड दस्तकारी की ट्रेनिंग के लिए जरूर लगना चाहिए ताकि कालेज से निकलने के काद उनको किसी ट्रैनिंग की जरूरत न पड़े अपने आप अनने काम में लग जाएं।

चौधरी ई वर सिंह (गुहला –अनुसूचित जाति): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, फ्लड की रोकथाम के लिये बजट में जो पेसा दिया है उसके लिये हरियाणा सरकार काबिले तारीफ है। लेकिन मारकंडा और टांगरी दो नदियां मेरे इलाके में बड़ी तबाही करती हैं इनका सारा पानी कुरुक्षेत्र जिले में इकट्ठा हो जाता है। टांगरी नदी से इस साल हजारों एकड रकबा तबाह हो गया और लगातार पिछले तीन सालों से ऐसा हो रहा है। इससे पहले ओलों की वजह से तबाही हुई और उसके बाद फलड ओ। जैसा कि सरकार का फजग है सरकार ने तीन किस्म की सहायत फल्ड से पीडित लोगां को दी। डिप्टी स्पीकर साहब, हर सरकार का फर्ज है कि रोटी कपडा और मकान से हर नागरिक की सेवा

करें। जनता सरकार का ने तीनों प्रकार की मदद कीं लोगों को रजाईयों दी गई, कम्बल दिए गए जिनको ट्रैक्टर की सहायता की जरूरत थी उनको वह भी दी गई। इस काम में मुख्यमंत्री जी का योगदान सबसे ज्यादा सराहनीय है और इन भलाई के कार्यों का श्रेय मुख्य मंत्री जी को ही जाता है। इनकी रहनुमाई के अंदर ही बांध बांधे गए, लोगों को ग्रांट दी गई, हर वर्ग को सबसिडी और लौन दिए गए। जिन लोगों को सहायता दी गई उनमें एक ऐसी भी जमात है जो गरीबी की लाईन में सबसे ज्यादा पिछडी हुई है। इस वर्ग के हर घर में गरीबी पैदा हो चुकी है। इनकी संताने मुख्यमंत्री जी को याद करेंगी कि उनके लिए चौपालें बनाई गई। यह श्रेय मुख्यमंत्री महोदय को जाता है कि इस वर्ग को सामाजिक रूप में, नैतिक रूप में और आर्थिक रूप में भरपूर मदद मिली है। इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे प्रांत के नजदीक राजस्थान और पंजाब प्रांत लगते हैं। इन प्रांतों के कालेजौं में हरिजनों के लिए स्पै ाल होस्टल बनाये हैं जहां पर हरिजन लड़के फ्री रहते हैं और ि ाक्षा ग्रहण करते हैं। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार के होस्टल हरियाणा में भी बनाये जाने चाहिएं ताकि हरिजन बच्चे भली प्रकार से ि ाक्षा ले सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, अनुसूचित जातियों के बारे में कोई डिमांड नहीं रखता लेकिन जैसे पोहलू साहब ने कहा था कि रिजर्वे ान इंकम के आधार पर होनी चाहिए। उसी तरह मैं भी

सरकार से बेकारी भत्ते की मांग करता हूं। सबसे पहले हमें सामाजिक बराबरी चाहिए और यह बराबरी तभी आ सकती है। अगर सब लोग आर्थिक रूप में बराबर हों। जिस प्रकार पंजाब ने बेकारी भत्ते का एलान किया है उसी प्रकार हमारी सरकार को करना चाहिए। बी0ए0, एम0ए0 पास लडके आज बेकार फिर रहे हैं। कोई गरीब मां बाप अपने बच्चों को पढाता है और यह सपना देखता है कि उनके बच्चों का जीवन खु ाहाल होगा लेकिन मैट्रिक, बी0ए0, एम0ए0 पास करने के बाद नौकरी से वंचित रह जाते हैं और बेकार घूमते हैं। ऐसे लड़को को बेरोजगारी भत्ता मिलना आव यक है नौकरी न मिलने के कारण कई बार बच्चे तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिये सरकार को बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। और जो बेकार हैं उनके लिए बेकारी भता दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछडे वर्ग की रिजवेशन सरकार ने 2 परसैंअ से 5 परसैंट कर दी है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं लेकिन अफसोस इस बात का है कि रिजर्वे ान की रे ाो पूरी नहीं की जाती। सरकार ने निकयम जरूर बनाये हुये हैं लेकिन इम्पलीमैंटे ान नहीं होती चाहे रिजर्वे ान हो, चाहे प्रमो ान हो और चाहे डायरैक्ट रिक्रूटमैंट हो, अगर इम्पलीमैंटे ान ठीक नहीं होती तो किसी को कोई लाभ नहीं होता।

डिप्टी स्पीकर साहब, ि ाक्षा के क्षेत्र तें सरकार ने स्कूल अपन ग्रेड करके एक सराहनीय काम किया है। पिछले 13

सालसे स्कूल अपग्रेड नहीं हुए थे। लेकिन जनता सरकार ने 90 स्कूलों को अपग्रेड करके एक सराहनीय कार्य किया है। 14 हजार अध्यापकों को जो टैम्परेरी लगे हुए थे परमानैंट किया और एक नई जिंदगी दी। जब गर्मियों की लंबी छुट्टियां होत थीं तो उनको हटा दिया जाता था और उसके बाद छुट्टियां खत्म होने के बाद लगा लिया जाता था। जिस प्रकार फालतू जमीन को जब चाहा बो लिया जब चाहा खाली छोड़ दिया। वही सलूक इनके साथ होता था लेकिन सरकार ने इनको रैगुलर करके बडा सराहनीय कार्य किया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, बसों के बारे में थोडा सा कहना चाहता हूं। सरकार ने गुहला में 50 नई बसें बढ़ाने का विचार व्यक्त किया है। मामला अभी विचाराधीन है। इस साईड में रेल नहीं लगती बार्डर का एरिया है इस एरिये में सबसे ज्यादा बस स्टैंड होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में कई जगहों पर बस स्टेंड नहीं हैं। बसों की हालत बडी पतली है, इसलिये अच्छी और जयादा बसें मंजूर करके पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा राहत पंहुचाई जानी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक सड़कों का ताल्लुक है। 41 लाख रुपये की लागत से टांगरी पर पुल बनार, 3 करोड की लागत से जमनानगर में बना और इसी तरह से मारकंडे के ऊपर पुल बना लेकिन मेरा एरिया जो पंजाब के बार्डर के नजदीक लगता है वहां पर लाखों लोगों को आने जाने के लिए कोई पुल

नहीं। एक पुल है जो पंजाब के एरिय में पडता है। इसलिये मेरी सरकार से अर्ज है कि घग्गर नदी पर एक पुल बनायाजाए ताकि उसके नजदीक लगते हुए 55 गांवों को आने जाने में सहूलियत हो सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने ग्रामीण वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया है। आज तक देहाती वर्ग का नारा लगाकर उन्हें लुटा जाता रहा है, आजदी की हवा ऊपर के वर्ग ने ही ली है लेकिन देहाती नागरिक तक आजादी की हवा नहीं पहुंच सकी। हमारी जनता पार्टी की सरकार ने आजादी की हवा देहातों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए। मैं इसकी सराहना करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, किसानों के ऊपर 33 परसैंट जो लेंड टैक्स लगाया है, इसको जरूर वापिस लिया जाना चाहिए, छोटे जमीदारव इसका बोझ सहन नहीं कर सकते। इसके इलावा बसों के जो किराये बढ़ाये हैं, उसके साथ भी मैं सहमत नहीं हूं। बसों में गरीब आदमी सफर करता है इसलिये यह टैक्स मुआप किया जाना चाहिये। इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवावद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के ऊपर सारे ही एम0एल0एज0 ने अपने विचार इतने रख दिये हैं कि कोई बात कहने की गुंजाइ ा कम ही रही है लेकिन फिर भी कुछ कहना पडेगा। हाउस के सामने यह जो बजट आया है यह आर्थिक नीति के लिये एक नया मोड है। इस बजट में कृशि और इंडस्ट्री को जो बढावा दिया गया है जो उत्साह दिया

गया है यह उत्साह उस पूंजीवीद क्रांति को रोकता है जो दे ा के सिर पर हैगिंग स्वोर्ड के रूप0 में लटक रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, हर बजट अपना इतिहास रखता है और हर बजट का अपना ह ार भी होता है। The origin of the society in the old age' आने पैट्रिआरकल और मैट्रिआरमल थ्यूरी पढी होगीं उनके कबीलों के सरदार होते थे। उनका बजट होता था लेकिन उनका बंटवारा ठीक नहीं होता था। इसकी वजह से वे कबीले नेस्तनाबूद हो गए। उसके आगे चल कर आपने बाद ाहों और भाहन ाहों का हाल देखा। उनका और उनके बजटों का क्या ह ार हुआ वह भी आपने देखा। यही नहीं ईरान के आखिरी बाद ाह को भी उड़ता हुआ आपने अभी देखा होगा। अपने बच्चों को भी वह नहीं संभाल सका। 1947 से 176–77 तक हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी का बजट आया। (विघ्न) उस बजट ने आहिस्ता आहिस्ता लोगौं के दिमागों में एक पीसफुल क्रांति लाकर खडी कर दी और उस क्रांति ने यह जाहिर कर दिया कि आगे चल कर खूनी क्रांति भी आ सकती हैं (विघ्न) During the last 30 years there was a tug of war betwwn the rich and the poor. The Congress Party and the bureaucracy was on the side of the richi and the national income was never distributed eaually. The rich became more richer and the poor more poorer. उस बजट का यह ह ार हुआ कि जिस प्रकार ओले पडने से फसल बरबाद हो जाती है उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की हकुमत इस तरह उडी जैसे इस पर ओले पड गए हों। (विघ्न) तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको वह थ्यूरी

बताने जा रहा था कि जिसके बेसिज प0र यह बजट आया है। 'The Age of Continuity written by Drucker एक किताब है। इस राईटर ने बहुत अच्छे विचार इस पुस्तक में दिए हैं। इसने कहा है कि किसान सबसे पहले खु ाहाल होना चाहिए। उसकी खु ाहाली से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की खु ाहाली से मजदूर खु ाहाल होता है। इन सबकी खु ाहाली से दुकानदार और बाकी के लोग भी खु ाहाल होंगे। हमने उस थ्यूरी को लिया है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि वह जो कि बापू जी भविश्यवाणी है। 1942 में जब वे आगा खां के महल में कैद थे तो उनकी एक किताब बापू जी की कारावास सु ीला नैयर द्वारा लिखित 5 दिसम्बर 1942 को निकली। इसके पेज 191 की भविश्यवाणी यह है कि हर इंकलाव के साथ उत्साह और जागृति की लहर आती है और लोगों के मनों में बैठ जाती है। यह लहर हिन्दुस्तान के मनों में बैठती चली जाएगी और हिन्दुस्तान के लोग इस लहर के बाद एक पीसफुल क्रांति देंखेंगे। यह 1975 में हुई। फिर भी बात काबू में न आई तो हिन्दुस्तान के अंदर खूनी क्रांति होगी, गृह युद्ध होगा और इसकी वजह से हिन्दुस्तान के साम्राज्य का अंत हो सकता है। (विघ्न) तो इन दोनों थ्यूरियों की बात करने के बाद मैं अपने बजट पर आता हूं हमने इन दोनों थ्यूरीज के आधार पर इस बजट को तेयार किया है लेकिन अगर इस बजट को ठीक ढंग से इम्पलीमैंट नहीं किया गया तो यह हमारा दोश नहीं होगा। तो इम्पलीमैंट करने वाली जो हमारी म ीनरी है इसको यह याद रखना चाहिए कि इस

दे ा में खूनी क्रांति आने का आवाहन भी है। आज हिन्दुस्तान का किसान इतना तंग आ चुका है कि वह क्रांति करने के लिये तैयार है। जिस किसान ने इन कांग्रेसियों को इस तरह से मारा है कि ये कबर में से निकल नहीं रहे हैं उसी किसान ने हमें खडा किया है। उस किसान के हित में यह बजट बना है। अगर इस बजट की इम्पलीमैंटे ान में ब्यूरोक्रैटिक म ीनरी कोई रूकावट डालेगी तो जो क्रांति आएगी उसमे सबसें ज्यादा दद्दुःखी यह म ीनरी होगी। इसलिये स्पीकर साहब, आखिर में मैं यह कहूंगा कि हमारे जितने भी मिनस्टिर्ज हैं ये भी अपने कथनी और करनी में कोई फर्क न रखें ये अपनी फाईलें धरती के ऊपर जो नक ा है उसके मुताबिक बनाएं क्योंकि फाईल और ऐक्चुअल प्रैक्टिस में पाई जने वाली चीज का अंतर जब कम हो जाएगा तो लोगों को सुख मिलेगां (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, लैंड टैक्स वगैर की बात यहां आई। इसके बारे में मैं जैन साहब से यह कहना चाहता हूं कि –

न छेड़ ऐ वादे बहारी राह लग अपनी,

तुझे अठखेलियां सूझती हैं हम बेजार बैठे हैं।

(प्र ांसा)

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जैन साहब से कहता हूं कि साल, छः महीने हिन्दुस्तान के साम्राज्य को और जीन दो वरना इसके मरने का वक्त आ रहा है। ये जो टैक्स आपने लगाये हैं

इनको माफ कर दो क्योंकि ये किसान के हित में नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां एक खूनी क्रांति आएगी और उस क्रांति के हैड भी हम होंगे।

श्री मांगेराम गुप्ता (जींद): डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। कई दिनों से बजट के ऊपर यहां बहस चल रही है। ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से इस बजट की बड़ी तारफी की गई है। यह भी कहा गया है कि अपोजि ान बैंचिज को भी इसकी तारीफ करनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार जनता के वोट से बनती है। हर सरकार चाहे वह पहले बनी, अब बनी या आगे बने, का यह काम होता है कि वह जनता का काम करे। अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो कुदरती बात है कि इसकी बडाई होगी और अगर बुरा करेगी तो बुराई होगी। हमारे बड़ाई करने से कोई सरकार ठहर नहीं सकती। बडाई तो जब तक जनता नहीं करेगी तब तक कोई सरकार बन नहीं सकती और ठहर नहीं सकती। उपाध्यक्ष महोदय, 7 तारीख को जब बाबू मूल चंद जैन जी अपना बजट भाशण पढ रहे थे तो आपने देखा होगा कि वह बजट नहीं बल्कि जिस तरह से एक ड्रामे की रिहर्सल होती है उस तरह से बजट के ऊपर रिहर्सल की गई। आपने यह भी देखा होगा कि जिस वक्त इस सरकार के कारनामें सुनाए जा रहे थे तब तो मेजें थपथपाई गई लेकिन आखिर में जब ये टैक्स के बारे में पढने लगे तो बजट की कापियां फाड दी गई। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अगर सही मायनों में जैन साहब बजट पे ा कर रहे हैं तो इन्होंने जो मैनीफैस्ओं में वायदे किए थे कि जनता को राहत देंगे ये जितने भी टैक्स लगाये हैं इन सबको खत्म करना चाहिए। मैं एक बात और भी सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब स्टैम्प डयूटी बढी ट्रांसपोर्ट टेक्स बढा तो यहां हाउस में कोई आवाज नहीं उठी लेकिन जब आबियाना और मालिया बढ़ा तो बड़ा भाोर मचाया गया। ट्रांसपोर्ट का जो किराया बढा है वह भी गरीबों पर बढा है उसकी भी तो आवाज उठानी चाहिए थी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा में यह एलान किया था कि टैक्स नहीं लगेंगे। इलैक ान के टाईम ही नहीं बल्कि हाउस में भी और पब्लिक में भी वायदे किए थे कि हम कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते लेकिन फिर भी टैक्स लगाये जा रहे हैं।।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां इस बजट का 175 करोड रुपया किसानों पर खर्च करना चाहते हैं वहां पर 173 करोड रुपया भी खर्च कर सकते थे। जहां बजट में 12 करोड रुपये का घटा है वहां पर 14 करोड रुपये का घाटा हो जाता। किसानों पर टैक्स लगाने की क्या आव यकता थी, थोड़ा बहुत और घाटा बढ जाता। पिछले साल जब टेक्स बढाये तो उनको विदड्रा किया गया परंतु मेरी यह समझ में नहीं आता है कि जब एम0एल0एज0 नाराज थे तो वही एम0एल0एज0 आज हैं फिर दुबारा टैक्स लगाने की क्या आव यकता थी। सवा छः एकड पर मालिया माफ करने का सारा ड्रामा है। यह सब दिखाने के लिए किया गया है कि हम

टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं। बाबू मूलचंद जी ने टैक्स लगाया तो उन्हें यह कहा गया कि इनकी किसानों के साथ हमदर्दी नहीं है। मैं तो यहीं कहूंगा कि खाली नारे लगाने से गरीब का भला नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सन 1972 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था इसी प्रकार से आपने भी नारा दिया है। आपके केवल नारे हैं, गरीबों का भला नहीं हो रहा है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस खत्म हो गई इसी प्रकार से आप भी खत्म हो सकते हैं। आप लोग किसान का नारा दे रहे हैं लेकिन गांवों में लोग कई वर्गों मूं बंट गये हैं। आपस में लोगों में नफरत पैदा होती जा रही है। किसान को सही मायनों में कुछ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ नारे दिये जा रहे हैं। जनता पार्टी किसानों के वोटों से जीत कर आई है इसलिए किसानों के भले की बात करनी चाहिए। इनको ध्यान करना चाहिए कि किसान कहां पर लूटा। इन्होंने सही बीमारी का इलाज नहीं किया। डिप्टी स्पीकर साहब, मास्टर हुकम चन्द जी कह रहे थे कि जब किसान के घर में अनाज होता है तो मन्दा होता है, जब उनके घर से व्यापारी के पास चला जाता है तो तेज हो जाता है। ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका इलाज करना चाहिए। जब तक इलाज नहीं किया जायेगा तक तब लोगगों का भला नहीं हो सकता। पिछले दिनों सरकार ने बाजरे का भाव 85 रुपये क्विंटल मुकर्रर किया परन्तु सरकारने एक क्विंटल भी बाजरा नहीं खरीदा। 70–65 रुपये क्विंटल बाजरा किबा। इसी तरह से आप गन्ने और गुड की बात लीजिए। आप विचार करें कि पहले गुड

70–65 रुपये क्विंटल बिका और अब 100–110 रुपये क्विंटल बिक रहा है। सरकार ने सही बीमारी को नहीं पकड़ा। सरकार ने गन्ना उगाने वाले किसानों को चार करोड रुपये की सबसिडी दी है। इस सबसिडी का केवल 20 परसैंट किसानों को लाभ होगा। में उन 20 परसैंअ किसानों का विरोध नहीं करता। यह लाभ वहीं होंगा जहां पर गन्ना मिल है। सरकार इस चार करोड रुपये से इस 15 लाख गुड के कट्टे खरीद सकतीज थी। अगर हम 100 रुपये क्विंटल के भाव से इस गुड को खरीद लेते तो सभी किसानों को लाभ हो सकता था। इस चार करोड की सबसिडी से सभी किसानों को कुछ न कुछ मिलता। इसी प्रकार से जीरी की हालत हुई। सरकार ने जीर का भाव 87 रुपये क्विंटल मुकर्रर किया परन्तु बाजार में 83–84 से एक पैसा भी महंगी नहीं बिकी। कनक की सरकार ने पाच छः क्वालिट बनायी थी।। 107 से 112 रुपये क्विंटल तक भाव मुकर्रर किया गया लेकिन सरकार ने 110 रुपये के भाव से गेहूं खरीदा। करोड़ा रुपये का जमीदारों को घाटा हुआ। सरकार सही भाव पर खरीदती तो करोडों रुपये का किसानों को लाभ हो सकता था। मैंने ये बातें किसानों के फायदे के लिए बताई हैं। किसानों पर जो टैक्स लगाया है यह बिलकुल गलत लगाया है। यह सारा ड्रामा है और पालिटिकल रंग देने के लिए सब कुछ किया गया। सरकार को ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए। सब लोगों को बराबर समझना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री जी को और जैन साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि हलवाईयों पर किसानों पर जो टैक्स लगा है और जो परसैंट टैक्स बढा है यह सब खत्म किया जाना चाहिए। हलवाईयों पर अगर यह टैक्स नहीं हटा तो वे सरकार का मुकाबला करने के तैयार बैठे हैं उनमें बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। इसी प्रकार से सफर हर गरीब आदमी करता है, अमीर बसों में नहीं चलते। अगर सरकार ने इन टैक्सों को वापिस नहीं लिया तो उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा।

मैं अर्बन डिवैल्पमैंट के विशय में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे बहुत से भाई भाहरों के बाहर बसे हुए हैं। वे भाहर से कुछ फासले प0र हैं। मैं इस बात को मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि दस बारह साल पहले जो भाहर था उसकी बाउंडरी के बाहर 25–30 परसैंट आबादी बढी है। भाहरों के बाहर जितनी भी कालोनियां बनी हैं। वे सब गांवों से जाकर लोगों ने बनाई हैं या कोई सरकार मुलाजिम हैं उन लोगों ने मकान बनाये हैं वकीलों ने भी कुछ बनाये हैं आज गावं के अंदर किसी भी गांव में चले जायें वहां की सभी गलियां पक्की हैं लेकिन जो भाहरों के बाहर कालोनियौं में रहते हैं उनमें 90 परसैंट गलिया कच्ची मिलेंगी। जहां आप देहात में इतना बढावा देना चाहते हैं वहां भाहरों के बारह जो कालोनियां बनी हुई हैं। उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वहां पर गलियां पक्की होनी चाहिए पानी का प्रबंध होना चाहिए।

एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार या इस सरकार की तरफ से म्युनिसिपल कमेटी के एरिया में अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर बोर्ड लगाता है तो उस पर टैक्स लगा हुआ है। आप यह देखिए कि इंकम टैक्स डिपार्टमैंट और सेल्ज टैक्स डिपार्टमैंट दोनों ही यह कहते हैं कि कोई आदमी टैक्स पे करता है तो उसकी दुकान के आगे बोर्ड होना चाहिए ताकि अफसर को तला ा करने में कोई दिक्कत न हो लेकिन म्युनिसिपल कमेटी ने बोर्ड पर ही टैक्स लगा दिया है। अगर कोई बडी मिल के मालिक हैं, फैक्टरी के मालिक हैं वे अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई बोर्ड लगाते हैं तो उन पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी दुकान पर या अपने मकान पर बोर्ड लगाता है और उस पर अपना नाम लिखवाता है तो उस पर टैक्स लगाना गैर वाजिब है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके सारे के सारे टैक्स वापिस लिए जाएं।

श्री भले राम (बडौदा–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं 1979–80 के बजट का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। सरकार ने कुछ टैक्स लगाए हैं लेकिन इनमें से मैं कुछ टैक्सों का समर्थन नहीं करूंगा जैसे कि लैंड टैक्स है और पानी पर आबियाना है। मेरे कुछ साथियें ने भी कहा है कि ये टैक्स वापिस लिए जाएं और डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि इनको वापिस लिया जाए। सरकार को इस बारे में अव य

गौर करना चाहिए। यह बजट बड़ी सोच समझकर तैया किया गया है। जैसा कि हमारी सरकार ने कहा था कि हम किसान का देहात में रहने वाले का भला करेंगे। इस बजट में उसकी सही तस्वीर है। पहली जो कांग्रेस सरकार थी उसने किसान की तरफ देहात के रहने वाले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। पहले देहात में कच्चे मकान होते थे और किसान की लहलहाती फसल हुआ करती थी और उस समय लोग सोचा करते थे। कि कहीं बाढ न आ जाए और यह जो हमारी लहलहाती फसल है और रहने का जो सहारा है वह खत्म न हो जाए। आमतौर पर यह होता था कि बाढ़ आती थी और उन देहात में रहने वाले के स्वप्न खत्म हो जाते थे। मेरी सरकार ने आते ही बाढ की रोकथाम के लिए कदम उठाए और उसके लिए यह सोचा कि इस बीमारी को सदा के लिए खत्म किया जाए। मेरी सरकार ने बाढ को रोकने के लिए ड्रेनों की एक स्कीम बनाई। उसके लिए लिंक ड्रैन जरूर बना दी है लेकिन जहां वह ड्रेन गिरेंगी वहां पर जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है उनकी कैपेसिटी सरकार को बढानी चाहिए। मेरे हलके में ईसापुर खेडा एक ड्रेन है उसमें कई ड्रेनें आकर गिरेंगी। जब तक उस ड्रेन की कैपेसिटी नहीं बढाई जाती तब तक कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि पानी ओवर फ्लो होगा। इसलित मेरी प्रार्थना है कि एग्जिस्टिंग डेंज की कैपसिटी बढ़ानी चाहिएं

दूसरी बात यह है कि सरकार ने रिंग बांध बनाने की स्कीम भाुय की थी। लेकिन वे रिंग बांध कम्पली नहीं हुए हैं।

पहले वे रिंग बांध कम्पलीट किए जाएं हमारे यहां एक रिढाना बांध है वह इंकम्पलीट है। उसको पूरा किया जाना चाहिए बजासे इसके कि और रिंग बांध भ्ारू किए जाएं पहले पुराने बांध कम्पलीट किए जाएं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक निजामपुर गांव है। वहां पर पानी निकालने के लिए पम्प हाउस मंजूर किया हुआ है लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हुआ है जिक उसको बिजली का कनैक ान जींद वाले देंगे या गोहाना वाले देंगे। मैं कई अफसरों को भी मिल चुका हूं लेकिन अभी तक पानी निकालने के लिए बिजली का कनैक ान देने के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। मेरी आई0पी0एम0 साहब से रिक्वैस्ट है कि इसको जल्दी ऐक्सपीडाइट करें। हमारे सी0एम0 साहब ने यह ऐलान किया है कि हम पानी का इंतजाम करेंगे और इसके लिए वे पूरी कोि ा ा कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं तकि एस0वाई0एल0 पर बातचीज चल रही है और मुझे पता है कि आई0पी0एम0 साहब चीफ मिनिस्टर साहब के साथ किस प्रकार से अपना केस प्लीड कर रहे हैं और पूरी कोि ा ा की जा रही है कि हमें पानी का पूरा हिस्सा मिल जाएगा तो हरियाणा का एक खूड भी बाकी नहीं रहेगा जहां पानी नहीं। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि जहां जहां नहर पक्की की जाएं उसके साथ साथ पानी को निकालने के लिए क्योंकि अब फ्लड आता है तो नहरों में ज्यादा पानी आ जात है और वह इधर उधर बहने लगता है पम्प लगाए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, बंसी लाल ने रोहतक और सोनीपत की नहरों के पानी में चालीस परसैंट की कट लगा दी थी। उस कट को काफी समय हो गया

है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस कट को अब बहाल किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आ वासन दिया था कि जो नहरे पक्की की जा रही है। वहां पर घाट बनाए जाएंगे। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर घाट बनाए जाएं। जब पानी बढ़ेगा तो किसान की पैदावार भी बढ़ेगी। सरकार ने 1979–80 के लिए 60 लाख टन अनाज का लक्ष्य रखा है। यह ठीक है कि छोटे किसान पर टैक्स माफ किया है। मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि खाद पर ज्यादा सबसिडी दी जाए। सरकार से एक और भी प्रार्थना है कि साढे छाः एकड वालों को जिप ाम पर छूट दी जाए।

इसके साद साथा मैं ि ाक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि सरकार ने पिछले साल एक सौ ग्यारह स्कूल अपग्रेड किये हैं और अगले साल 180 स्कूल और अपग्रेड करगी। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में ि ाक्षा का स्तर बहुत गिरा है। कांग्रेस सरकार के जमाने में टीचर्ज को बहुत ज्यादा डिमोरेलाइज किया गया था, उनको सरेआम जलसों में कहा जाता था कि इन टीचर्ज को पीटो। उस से पढाई का ढांचा गिर रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ि ाक्षा के स्तर में सुधर किया जाए और खासतौर से प्राईमरी ि ाक्षा के स्तर में सुधार लाया जाए। अगर प्राईमरी ऐजूके ान में सुधार हो जाए तो मैं नहीं समझता कि ऐजूके ान का स्टैंडर्ड गिरेगा। एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यह ठीक है कि सरकार चौपाल बना रही है और मैं

समझता हूं कि सब से कम चौपाल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बनी हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में छिछडाना और नूर खेडा गांव के लोगों ने चौपालों के लिए दस दस हजार रुपया जमा करा दिया है लेकिर अभी तक मैंचिंग ग्रांट नहीं मिली है। चौधरी प्रीत सिंह हमारे याहं चौपाल का फाउंडे ान स्टोन भी रख कर आए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने एलान किया है कि अगर किसी गांव के लोग चाहेंगे कि वहां पर दो चौपाल हों तो वहां पर दो चौपाल बनाई जाएंगी। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे यहां जल्दी से जल्दी मैंचिग ग्रान्ट दिलाई जाए और सरकार ने पानी पर टैक्स लगाया है या जमीन पर टैक्स लगाया है उसको वापिस लिया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री जय नाराण (कलानौर –अनुसुचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया है। कई दिनों से बजट पर चर्चा चल रही है और कांग्रेस (आई) के मेरे माननीय साथियों ने बडी हमदर्दी के साढथ अपनी भाोक भरी कहानी पे ा की और ऐसा जाहिर किया कि किसान, मजदूर और बैकवर्ड क्लास के भाइयों ो उनको बहुत ज्यादा प्रेम है। ऐमरजैंसी के दौरान इन भाइयों ने इनके सवाथ बहुत ज्यादा प्रेम दिखलाया था और इन भाइयों की बहुत ज्यादा सेवा की थी। पीपली कांड में जब कि वहां लाखों लोग इकट्ठे हुए थे तो इन भाइयों ने किसान मजदूर और गरीब भाईयों की बडी सैवा की और रिवासा के अंदर भी इसी तरह के कांड हुए थे

लेकिन आज ये बडी हमदर्दी की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से जब से जनता पार्टी की सरकार आई है उस दिन से जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस सरकार बजट का 17 परसैंट देहता पर खर्च किया करती थी और सैंट्रल सरकार ने देहात पर चालीस प्रति ात करने का फैसला किया है। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल ने 75 प्रति ात पैसा देहात पर खर्च करने का फैसला किया है। यह बधाई की बात है। आज हरिजनों की भलाई के लिए काफी काम किए जा रहे हैं। दो तीन महीने पहले से कांग्रेस वाले देहातें में जाकर लोगों को बहकाते थे और गरीब किसान और मजदूरों के बीच लड़ाई कराते थे। ये लोग वाहं जाकर हरिजन और गैर हरिजनों के बची दराड़ पैदा करते हैं और गलत प्रचार करते हैं। हरिजनों और नान हरिजनों का मसला सब इन्हीं कांग्रेस भाईयों की ही मेहरबानी का नतीजा है। इन्होंने ही यह सरे मसले भ्ारू कर रखे हैं और देहातों और भाहरों के अन्दर जो इस किस्म की फिजूल की बातें की जा रही हैं, वह भी यही कांग्रेसी लोग ही करवा रहे हैं क्योंकि वह इस जनता पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें यह नहीं पता कि यह जनता पार्टी इतनी मजबूत बन चुकी है कि सदियों तक भी इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। (तालियां) जनता पार्टी बहुत मजबूत बन चुकी है। इन कांग्रेसी भाईयों के ये स्वपन कभी भी पूरे नहीं होंगे। ये भाई तो एक ही कौम के दो टुकडे करना चाहते हैं ऐसा इन भाईयों का पिछले तीस सालों का तर्जुबा है। (ाोर) उपाध्यक्ष

महोदय, मैं आपको बताता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय चौधरी देवी लाल जी अमूमन गांवों में लोगो से मिलने जाते हैं और वहां से जितनी भी मालाएं उनके गले में डाली जाती हैं, वह उस हजारों रुपये को उसी गांव की बहबूदी के लिये ही वहां पर दे आते हैं पर 1968 में जब चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त की बात मैं आपको बताता हूं। मेरे हलके में एक गांव है। वहां पर लोगों ने उन्हें एक स्कूल को अपग्रेड करवाने के लिये 25 हजार रुपये की रा ि ा माला के रूप में भेंट की तो चौधरी बंसी लाल जी उस को झट से अपनी कार में रखकर चल दिये। तो यह इन भाईयों का प्यार था।

श्री भाम ोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ऐलीमे ान लगाया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत बात है कि स्कूल को अप ग्रेड करवाने के लिये वह पैसा दिया गया था। मेरी प्रार्थना है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप देना चाहिये। (ोर)

श्री जय नारायणः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोडा सा समय और दे दीजिये। अभी तो पारा गर्म हुआ है अभी तो मैंने बहुत सारी बातें कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्षः अब आप समाप्त कीजिये।

श्री जय नारायणः उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिये बातें तो बहुत हैं लेकिन चूंकि आपकी तरफ से बैठने के लिय

इ ारा हो रहा है इसलिए इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री देवी दास (सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त सदन में बजट पर बहस चल रही है जिसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने कुछेक बातें करके हमारे किसानों को काफी राहत दिलाई है। सवा छः एकड़ जमीन वाले किसान का मालिया बिल्कुल माफ कर दिया है। इसके साथ साथ में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 40 हजार से 1 लाख तक की सेल वाले जो छोटे दुकानदार हैं, उनको भी टैक्स की माफी दे दी गई है। यह हमारी सरकार ने बडा सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं। हमारी जनता सरकार ने ऐसे काम किये हैं जो कि पिछली किसी सरकार ने भी नहीं किये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि देहातों पर कोई खर्चा नहीं किया गया है लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बजट का 75 प्रति ात देहातों की भलाई के लिये ही खर्च किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि खाली नारों से ही काम चलाया जा रहा हो, हमारी सरकार ने कुछ सोलिड काम भी करके दिखाये हैं जो कि काबिले तारीफ है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहीं पर चले जाएं आप देखेंगे कि फ्लड के बचाव के लिये जगह जगह पर बांध और ड्रेनें बनाई गई हैं

ताकि गांवों के लोगों को फ्लड से राहत मि सके, ऐसा काम आज से पहले पिछली सरकार अपने 30 साल के राज में भी नहीं कर पाई थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देहातों में उद्योग लगाने के लिये 190 लाख रुपये खर्च करने जा रही है, जो कि एक बडी भारी अचीवमैंट है। यह अपने आप में एक बडी मिसाल है।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देहातों के इलावा भाहरों की तरक्की का भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिये मैं आपको मिसाल देता हूं कि सोनीपत के लिए मुरथल में एक वाटर सप्लाई स्कीम काफी दे से खड्डे में पडी हुई थी, अब उसको भी चालू कर दिया गया है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री महोदय सोनीपत गये थे, उन्होंने वहां के सिविल हस्पताल को 100 बैडज का करने का एलान कर दिया है। इसी तरीके से सारे हरियाणा में जनता सरकार ने बडे अच्छे अच्छे काम किये हैं। यह बडा अच्छा और किसानों की भलाई का बजट है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा टैक्सों में किसान को गरीब आदमी को राहत दी जा सकती हो दी जानी चाहिए। सरकार ने आबियाना पर जो 10 परसैंट सरचार्ज लगाया है, वह भी माफ होना चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर साहब, मैं एक दो बातों का विरोध भी करता हूं। एक प्रकार से पैसेंजर टैक्स भी

माफ होना चाहिये। मैं एक बात और कहता हूं कि अगर अच्छी सरकार हो तो उसके बारे में लोग हमे ा हलवाईयौं की दुकानों पर चाय वगैरह पीते समय बातें करते हैं और इसी प्रकार से बसों में सफर करते समय भी बातें करते हैं। अतः मेरा सरकार से निवदेन है कि इन छोटे लोगौं पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगना चाहिये ताकि ये लोग सरकार की सरहाना करें और इस बजट को जनहित का कहें।

स्पीकर साहब, मैंने एक बात और भी बडी महसूस की है कि एमरजैंसी के वक्त सारे हरियाणा में काफी लोग पकड़े गये थे। जेल में ही कई लोगौं की बीमारियां हो गई। सोनीपत का एक वर्कर था जिसका नाम प्राणनाथ था उस बेचारे को अधरंग हो गया और अब वह किसी भी काम के लायक नहीं रहा। ऐसे ही हरियाणा के अंदर दूसरी जगहों पर हुआ है, इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे केसिज की तरफ भी ध्यान दें और ऐसे लोगों को कुछ राहत दी जाए ताकि वे लोग अपना जीवन निवार्ह कर सकें। इन लोगों ने हमारी सरकार के लिये और पिछली सरकार का अंत करने के लिये इतने दुःख सहे हैं। मुझे अपनी सरकार से पूर्ण आ ा है कि यह इस तरफ अव य ध्यान देगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा–

सदन के स्थगित होने के सम्बन्ध में दैनिक 'वीर प्रताप' में एक समाचार छपने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, जैन साहब की रिप्लाई से पहले मैं सदन में एक अनाउंसमैंट करना चाहता हूं।

It has been brought to my notice that reports have apperaed in a section of the press, particularly in "Vir Partap" a Hindi newspaper regarding the adjournment of the House on 21.3.1979.

I quote the relevant sentence from "Vir Partap". Referring to the speech by Dr. Mangal Sein, the Paper has reported as under :-

"अन्य सदस्यौं द्वारा इसका विरोध किये जाने पर बैठक को कल के लिए स्थगित करना पड़ा।"

I wish to point out that the implied meaning behind this statement is incorrect. The House was adjourned at the stipulated, normal hour of interruption, i.e. 13.00 hours. I would request the representative of the newspapers to ensure that the proceedings are correctly reported.

वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

17.00 बजे।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चार दिन से बराबर बहस चल रही है। चार दिन से ही नहीं बल्कि यह पांचवीं सिंटिंग है। अब तक 32 माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है और इनमें से कितनों ने अपने फाइनैंस मिनिस्टर साहब को बुद्धिमान, समाजवादी औ प्रगति ील कहा और कुछ दोस्तों ने उसे एंटी किसान भी कहा। मैं सभी सदस्यौं का चाहे उन्होनें कुछ भी कहा हो भाुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं मैं समझता हूं कि अगर इन पर वे खुद भी विचार करें और सरकार भी विचार करे तो हमारी स्टेट का जरूर फायदा होगां जहां तक अपोजी ान के माननीय सदस्यों की नुक्ताचीनी का संबंध है उसके बारे में मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर उनको पार्टी लाइन से परे हट कर सुझाव देने चाहिएं थे लेकिन मुझे अफसोस है कि अपोजी ान ने यह रोल अदा नहीं किया। जहां तक हामरी सरकार का ताल्लुक है अपोजी ान के भाई इस बात को मानेंगे कि वह मैरिट के आधार पर काम करती है। अभी श्री भाम ोर सिंह जी का चौधरी सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ प्रिविलेज मो ा के संबंध में एक अमैंडमैंट आया था जिसको हमने ठीक समझ कर स्वीकार किया। हम इस बात पर नहीं गये कि चौधरी भाम ोर सिंह अपोजी ान की तरफ से हैं इसलिये इनका मो ान न माना जाये। इसलिये मैं अब भी अपोजी ान के दास्तों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बजट को और इसमें जो सुझाव हैं उनको अच्छी स्पिरिट से देंखें। मुझे सात मार्च का ताज्जुब हुआ था जब अपोजी ान के लीडर राव बीरेन्द्र सिंह ने इस बजट को

बाहियात बजट कहा था लेकिन अब बहस में बोलते वक्त वे बाहियात का भाब्द इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि इस दौरान इनके अपने पेपर्ज में कुछ खबरें छपी। कुछ पेपर्ज कांग्रेस आई के है जैसे नै ानल हेरल्ड हैं यह इन्दिरा गांधी के कंट्रोल में चलता है और इसी तरह से मिलाप अखबार है जो पंजाब से निकलता है और य ा जी इसके सम्पादक हैं और भायद मालिक भी हैं। वे अखबार क्या कहते हैं वह मैं आपकी इजाजत से पढ कर सुनाना चाहता हूं। यह 9 मार्च 1979 का मिलाप अखबार है इसमें लिखा है।

"हरियाणा सरकार इस बात के लिये मुबारिक की मुस्तैहक हे कि उसने दलीरी और ईमानदारी से काम लिया है। बजट पे ा करते वक्त न तो लारे लप्पे से काम लिया और न किसी को धोखे में रखो। सवाल कि इस पहलू पर तो बहस हो सकती है कि कौन सा टैक्स लगना चाहिये और कौन सा नहीं। मगर वजीर खजाना बाबू मूल चन्द जैन ने बजट का घाटा पूरा करने के लिये जो मुनासिब समझा कर दिया। इन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उनकी अपनी पार्टी का क्या रद्दे अमल होगा।"

इसके बाद एक पैरा छोड कर लिखा है –

"कठिनाई सिर्फ चौधरी देवी लाल की अपनी ही नहीं थी, अपने नये वजीर खजाना बाबू मूल चन्द जैन को भी थी। बाबू

मूल चन्द है तो वकील मगर उनका संबंध भाहरियों और व्यापारियों से है। उन पर यह इल्जाम आ सकता था और यह इल्जाम उन पर लगाया भी गया कि इन्होंने किसान मार बजट पे ा किया है।"

इसके बाद एक पैरा छोड कर लिखा है –– (विघ्न) ये पैरे बीय में मैं इसलिये नहीं छोड रहा कि इनमें आपेक (अपोजी ान की तरफ इ ारा करते हुए) मतलब की बात है बल्कि मैं तो हाउस का समय बचाने के लिए छोड रहा हूं। आगे लिखा है –

"लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हरियाणा सरकार का बजट न सिर्फ सियासी चोंचलेबाजी से आजाद है बल्कि यह हर लिहाज से एक मुतवाजन बजट है। टैक्स किसी पर भी लगाये जाये वह बोझ महसूस करता ही है और यह कहना भी अपने आप को धोखा देना है कि हम तो अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। कोई सुबाई टैक्स ऐसा नहीं होता जो सिर्फ अमीरों पर लगे।" इससे आगे अखबार लिखा है: "हरियाणा सरकार ने आबियाना और मालियाना पर जो सरचार्ज लगाया है इसका बोझ छोटे किसानों पर कम है बडे जमींदारों पर ज्यादा और इस बोझ का तवाजन बनाये रखने के लिये सवारी टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। जजबात और पक्षपात से ऊपर उठकर देवी लाल वजारत में बोझ बांटने की कोि ा ा की है।"

इसके बाद मैं 10 मार्च के नै ानल हेरल्ड का भी एक छोटा सा पैरा पढ़ना चाहता हूं। पहले उसमें पंजाब के बजट पर विचार दिये गये हैं। फिर बाद में हरियाणा के बजट पर इस प्रकार से विचार दिये हैं ––

"The Haryana budget, on the contrary, is more modest. The taxation package of Rs. 20 crores leaves an uncovered deficit of around Rs. 12 crores. The State Fincace Minister, Mr. Mool Chand Jain, has shown guts in announcing a levy of 33.3 per cent surcharge on land holdings measuring more than 6.25 acres and in imposing a surcharge of ten per cent on water rates to enable teh irrigation works to cut their losses. In view of the strom of protest which these new levies have raised even within the Janata Legislature Party, it is too early to say whether they will be approved by the Assembly without any changes. The icrease in bus fares, which will net the state exchequer around Rs. 3.4 crores, ws inevitable in view of the rising cost of road transport operations. The other imposts are comparatively light and non controversial."

स्पीकर साहब, मैंने ये दो कोटे ांज इसलिये दी हैं ताकि यह पता चल सके कि हमारे जो अपोजी ान के भाई हैं ये इस हाउस में क्या कहना चाहते थे और बाहर हमारे हरियाणा की जनता को क्या कहना चाहते थे। माननीय साथी चौधरी भाम ेर सिंह जी ने कहा कि इस बजट को जो किसानों की भलाई का बजट नहीं है। तो स्पीकर साहब, मैं उनको थोडे से आंकडे बताना चाहता हूं कि यह बजट कैसे किसानों और देहातियों की भलाई

का बजट है। हमारा प्लान आउट ले 227.30 करोड का है। इसमूें से जो हम अगले साल देहात की भलाई के लिये खर्च करने जा रहे हैं वह 191.31 करोड की रा ि ा है इसमें से कुछ रा ि ा तो बिजली पर खर्च होगी जो कि मु तरका तौर पर भाहरों के लोगों के भी काम आती है और देहात के लोगों के भी काम आती है। इसके अलावा जो मैं दूसरे आंकडे रखूंगा वे सभी देहातों के लिये हैं। जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसिज हैं इसके लिये 29.19 करोड रुपया रख गया है। इरीगे ान प्रजैक्टस पर 63.15 करोड रुपया रखा गया है, एम0आई0टी0सी0 के लिये डेढ करोड रुपया रखा गया है, फ्लड कन्ट्रोल प्राजैक्टस के लिये 20 करोड रुपया है और पावर प्राजैक्टस के लिये 57.52 करोड रुपया रखा गया है। इस तरह से कुल मिला कर 171.36 करोड रुपया बन जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री जो केवल देहातों में लग रही है इसके लिय 2.06 करोड रुपया रखे गये हैं। अभी 15 मार्च को इंडस्ट्री की स्कीम का अपने अपने हलके में मैंबर साहेबान ने उदघाटन किया है। जो भाहर में इंडस्ट्री लगी हैं उसकी फिग्गर अलग है वह इसमें भाामिल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों को एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े मैंने इंडस्ट्री के दिये हैं ये केवल देहात के हैं। अगर भाहर की इंडस्ट्री भी इसमें भाामिल की जाए तो चार करोड रुपया बनता है। इसलिये जो मैं 2.06 करोड की फिग्गर बता रहा हूं वह केवल देहात की है। यह रकम कर्जा देने की भाकल में या दूसरे साधन मुहैया करने पर खर्च होगी। इसी तरह से रोडज और ब्रिजिज पर 6.67 करोड रुपये, ऐजुके ान पर

1.29 करोड रुपये, मैडिकल पर 0.88 करोड रुपये और पब्लिक हैल्थ सैनीटे ान और वाटर सप्लाई पर 7.78 करोड रुपये रखे गये हैं। हाउससित के लिए 60 लाख रुपये, ि ाडयूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासिज के लिए 66 लाख रुपये, इन सबका टोटल 191. 31 करोड बनता है। इसके अलावा 1 करोड रुपया देहताम में चौपालें बनाने के लिए रखा गया है जो विभाग के अफसरों की गलती से या किसी प्रकार से रह गया है उसको मिलाकर 192.31 करोड रुपया बना। बजट का टोटल आउस ले 227.30 करोड का है जैसे कि पहले बताया गया है इसका 85 प्रति ात अमांउट देहात में खर्च होना है। सन 1971 की मर्दम ुमारी के मुताबिक देहात की पापुले ान 82.34 प्रति ात और भाहर की 17.66 प्रति ात बनती है। इसके मुताबिक भी अगर देखा जये तो यह बजट बिलकुल ठीक है। आबादी के लिहाज से ही बजट में प्रोवीजन किया गया है। स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह देहाती भाईयों पर कोई अहसान नहीं है, उनके प्रति हम अपने कर्त्तवय का पालन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बजट बुद्धिजीवीयों के दिमाग की उपज है। पिछले तीस वर्शों में भी जितने बजट बने हैं वे इन बुद्धिजीवियों द्वारा ही बनाये गये हैं आपका मालूम है कि बुद्धिजीवियों की ज्यादा संख्या भाहरों में है देहात में बहुत कम है। पीरछे जितनी भी पंचवर्शीय योजनाएं बनी हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और अब यह छठी चल रही है, इन सबमें ज्यादा फायदा भाहरी अमीर लोगों को हुआ है, देहात के लोगों को कम हुआ है। आप को पुरानी एक मिसाल बताता हूं।

पहले देहातों में जब बारात उस गांव से विदा हो कर चलती थी तो वे ताम्बे के पैस दवन्नियां, चवन्नियां आदि की बिखेर करते थे लेकिन अब यह रिवाज कम है।

आवाजें: बनियों में करते होंगे।

श्री मूल चन्द जैन: मैने तो सब बिरादरियों में ऐसा देखा है और यह बात सभ पर लागू होती है। (विघ्न) तो स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जब बाराती बहू को डोले में बिठा कर चलते थे तो वे पैसों की बिखेर करते थे और उर रेजगारी को बरीब बच्चे उठा लेते थे। इस बिखेर का फायदा यह होता था कि गांव में बसने वाले गरीब बच्चे इन पैसों को बटोर लेते थे और उनके दो रुपये से 5 रुपये तक बन जाते थे। यह उनकी एक प्रकार की मदद होती थी। आपके देखने में यह भी आया होगा कि किसी किसी बारात में चार मु ांटंडे चादर को लाठियों से बांध लेते थे और जो बखेर की जाती उसको ऊपर ही ऊपर ओट लेते थे। गरीब बच्चों को उसका एक भी पैसा नहीं मिलता था। स्पीकर साहब, पिछले 30 वर्शों में भी आए साल बजट में इसी प्रकार होता था। मेरे ख्याल से भारत में सालाना अरबों रुपया खर्च किया जाता था और यह अरबों रुपये भाहरी और कुछ देहाती बुद्धिजीवी भी मु ाटण्डों की तरह समेट लेते थे। देहाती लोगों को इस पैसे से कुछ खास फायदा नहीं होता था। इन प्लानों का उनको फायदा होता था जो भारत में बसने वाले एलाईट हैं, बुद्धिजीवी हैं। एलाईट भी दो प्रकार के हैं– धनी और निर्धन। इन बुद्धिजीवियों

में से गरीब बुद्धिजीवी भी है जो बेकार हैं, एम0ए0, पी0एच0डी0 करके बैठे हुए हैं लेकिन उनको कोई भी नहीं पूछता था।

आवाजें: बुद्धि जीव किस प्रकार के होते हैं ?

श्री मूल चन्द जैन: अगर मुझे यह भी समझाना पडेगा तो बडे भार्म की बात है। आप हरियाणा की जनता के प्रतिनिधि बने बैठे हो, आपको यह मालूम होना चाहिये वरना आपके पदों को विदड्रा करना पडेगा। स्पीकर साहब, मैं कह रथा था इन सारी योजनाओं का फायदा भारत में बसने वाले एलाईट को हुआ। भाहरों में असने वाले गरीबों को भी फायदा नहीं हुआ है। देहात में बडे वर्गों के लौगों को भी इसका फायदा हुआ है।

श्री भाम ोर सिंह: क्या अब यह प्रौसैस बंद भी हुआ या नही ? (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन: जब आप के अपोजी ान के भाई बोल रहे थे तो मैं बड़ी भान्ति से सुन रहा था। मेरा विचार था कि कोई न कोई भाई अपने प्रगति ील विचारों में इस प्रौसेस को बदलने के लिए बतायेंगे ताकि हमारी सरकार इसको सुधारने में कामयाब हो सके। पहले बुद्धिजीव इस प्रकार का बिहेव करते थे कि वे आम जनता को तो कुछ जानते ही नही थे। कांग्रेस सरकार ने अनेकों योजनाएं बनायीं। 24 साल पहले कांग्रेस सरकार ने दे ा के सामने उद्दे य रखा था कि समाजवादी समाज की स्थापना की जायेगी, किसी का किसी प्रकार का भाोशण नहीं

किया जायेगा। परन्तु इस लक्ष्य के रखने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार कामयाब नहीं हुई। नार्वे के बडे भारी अर्थ ाास्त्री गैनार मरडेल उनकी पत्नी भी अर्थ ाास्त्री हैं, पंडित जवाहर लाल जी के समय में वे भारत आये थे, वे कई बार हिन्दुस्तान आये, भाायद आखिरी बार 70–71 में आये। उस वक्त जो उन्होंने कहा था वह मैं अपने साथी भाम ोर सिंह जी से बतलाना चाहता हूं। उस समय कांगेस का सितारा बुलंदी पर था। उन्होंने कहा था–

"The tragedy of theis courntry is that the elites talk of socialism and of establishing an egalitarian society, but wheneverr any step is taken in that direction, they oppose it tooth and nail."

तो गैनार मरडेल ने कहा कि वह पैसा एलाईट वर्ग को ही जाता है। अब वे एलाईट उन दिनों को याद कर रहे हैं। अब उनकी सरकाद बदल गई है और हमारी सरकार ने करवट ली है। इस करवट का नक ाा अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी हाल ही में 15 मार्च को जो ग्रामीण उद्योगीकरण के जलसे हुए हैं उनसे देख सकते हैं।

श्री भाम ोर सिंहः आप भी तो उसी कांग्रेस को छोड़कर आये हैं

श्री मूल चन्द जैनः इसी वास्ते छोड कर आया हूं कि जो उनका लक्ष्य था, जिन आद ार्ों पर उनको चना चाहिये था, उन पर नहीं चले। हमने खु ी खु ी उन आद ार्ों के लिए

कुरबानी भी दी थी। उन आद ार्शों के लिए ही हम 19 महीने आप की चहेती इंदिरा गांधी की जेलों में रहे। उन्होंने उन आद ार्शों पर अमल नहीं किया ?

श्री भाम ोर सिंहः जेलों में जाने का नतीजा क्या निकला ?

श्री मूल चन्द जैनः नतीजा भी अभी आपको बतला रहा हूं। स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि इस दे ा में बसने वाले गरीब आदमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब हम उनकी सेवा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उस प्रोग्राम की एक झलकी मैं आपको बताता हूं। स्पीकर साहब, इनका वह जमाना था जब कोई गरीब आदमी कर्जा लेने के लिये बैंक में जाता था तो बैंक वाले कहते थे कि यह कर्जा वापिस कैसे करेगा ? इसी तरह दरमियाना दर्ज के लोग भी जब कर्जा लेने जाते थे तब वह भी परे ाान होते थे लेकिन 15 मार्च को हमने अपनी आंखों से देखा कि बैंको के कर्मचारी जैसे स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नै ानल बैंक और दूसरे बैंक अब किसानों के घर घर में जा करके यह कहते हैं कि आप बैंक से 4 परसैंट सूद पर कर्जा लें। यह क्रांति का स्वप्न हम अपनी स्टेट में सफला होता देख रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अभी मंजिल देर है लेकिन मेरे कांग्रेस पार्टी के भाईयों ने तो पडाव को ही मंजिल समझ लिया था क्योंकि राजनैतिक आजादी पडाव है मंजिल नहीं। इन्होंने अपने लक्ष्य के पडाव को ही मंजिल समझ लिया था।

इसलिए यह आराम करने लग गये, इस कारण से ही हमने उनका साथ छोड दिया। हमने इनसे कहा कि हम इस सफर के राही नहीं है, स्पीकर साहब, देहाती भाईयों की ओर जो भाहरों में बसने वाले गरीब भाई हैं उनकी भलाई के लिए 85 परसैंट रुपया रखा है। हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया बल्कि हम तो अपने कर्त्तव्य को निभा रहे हैं। जब हम उनकी भलाई का काम करते हैं तो हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं आती, बल्कि यह हमारा लक्ष्य है। यह प्लान उनके प्रति ही नहीं है बल्कि दे ा के प्रति है। जब हमारा गरीब मजबूत होगा तो दे ा भी मजबूत होगा। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, 'The strength of a chain does not lie in its strong link but in its weakest link.' एक जंजीर की मजबूती उसकी मजबूत कडी पर निर्भर नहीं होती बल्कि उसकी कमजोर कडी पर होती है। जितना हम कमजोर कडी को मजबूत करेंगे उतनी ही ज्यादा वह जंजीइर मजबूत होगी। इसलिए हमने अपना यह लक्ष्य रखा है कि देहाते के लिऐ भाहरों के गरीबों के लिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा रुपया हम जुटा सकें जुटायें और जितनी भी प्लान बना सकें उतनी बनाएं। जनता सरकार आने के बाद हमने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए प्लान बनाई है। स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने इसके बारे में नुक्ताचीनी की है और श्री मांगे राम गुप्ता जी ने जिस दिन मैंने अपना बजट भाशण पढा उस दिन के वाक्या को एक ड्रामा कहा है। मैं श्री मांगे राम जी को बताना चाहता हूं कि इस ड्रामे में हम सभी भाामिल हैं। लेकिन जो हमारी बजट प्रपोजल्ज हैं, उनको हमने

हाउस के सामने इस ढंग से रखा था कि वे फाइनल नहीं थी। हमने हाउस की स्वीकृति के लिए रखीं ताकि हाउस उस पर विचार कर सके। उस पर चार दिन बहस हुई। मैंने जनता की और माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया देखी। उस प्रतिक्रिया के हिसाब से आज भी सुझाव बदला जा सकता है और हमने बदला भी है। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मैंने जो अखबार हाउस में पढे हैं जैसे पंजाब केसरी, वीर प्रताव, नव भारत टाइम्ज और ट्रिब्यून सब ने बजट की सराहना की है और श्री वासुदेवा झा ने तो नवभारत टाइम्ज में 10 राज्यों के बजट को कम्पेयर करके हरियाणा के बजट की प्र ंसा की है। स्पीकर साहब, आपको यादा होगा जब मैंने अपने बजट प्रस्ताव में यह पढा था कि 36 करोड के घाटे में से 14 करोड रुपए की रकम ऐसी है जो कि हमें भारत सरकार से मिलने की आ ा है। पिछले साल का घाटा सिर्फ 14 करोड रुपए के लगभग का रहता है, इसलिए यह रुपया हमें भारत सरकार दे देगी और हम चालू वित्त वर्श में सिफर के घाटे के बराबर से चलेंगे। मुझे खु ी है कि हमारी हरियाणा सरकार ने यह हिम्मत की और बजट में जो हमने सुझाव दिए हैं उनको लेकर हमारे कर्मचारी और हमारे अफसर साहेबान भारत सरकार के पाए गए। इस बजट के सुझावों को देखकर वे भारत सरकार ने कहा कि वाकई हरियाणा सरकार ने बडी हिम्मत की है। स्पीकर साहब, मैं बडी खु ी के साथ हाउस को बताना चाहता हूं कि वह 14 करोड रुपए के घाटे को पूरा करने की बात है लेकिन इस बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाराब के ठेके पिछले साल

लाटरी सिस्टम से अलाट किये थे लेकिन इस साल नीलाम किये जायेंगे। पिछले साल गलती हो गई थी और उस गलती को हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। श्री बलवंत राय तायल ने भी यह कहा कि मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने अपनी गलती मानी है यह उनके बडप्पन की बात है। उन्होंने इस बात को भी माना कि अब यह गलत पालिसी छोड दी है। इस बारे ठेके नीलाम हुए। हमें वि वास है कि इस नई पालिसी के हिसाब से 5–6 करोड रुपए की आमदनी होगी। हमने एस्टीमेट लगाया था कि ऐसा करने से इस अगले बजट में ज्यादा आमदनी होगी और उस आमदनी को देख कर हमारी पार्टी की जो कमेटी थी उसने भी इस बात पर जोर दिया और बाकी सदस्यों ने भी यह चाहा कि इनता रुपया जब आपको मिलता है तो उसको आपने बजट के 227 करोड रुपए प्लान साधनों में भामिल क्यों नहीं किया। इसलिए कम से कम 5–6 करोड रुपए प्लान साधनों में भामिल क्यों नहीं लगाया था वहां हमें आले पडने का भी ख्याल नहीं था। हमारे हरियाणा में ओले पडे। हरियाणा सरकार उन किसान भाईयों को पूरा मुआवजा तो नहीं दे सकती लेकिन जिस फराखदिली से हरियाणा सरकार ने औले से मारी हुई खेती का मुआवजा देने की घोशणा की है, इतना मुआवजा आज तक कभी भी किसी भासन में नहीं दिया गया। स्पीकर साहब, सिर्फ यही नया खर्च नहीं आया है। अभी हमारी सरकार ने पे कमी ान मुकर्रर किया हैं पे कमी ान के लिए पंजाब सरकार ने तो अपने बजट में वोट आन अकाउंट पास किया है। उन्होंने 6 करोड रुपये रखे हैं, अगर वे पंजाब ने टैक्सों

के सुझाव नहीं दिए क्योंकि वह अपने गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में लगे हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के पे कमी ान से जो वेतन बढेंगे और डीयरनैस अलाउंस वगैरह बढेंगे उसको हमने इस बजट में नहीं रखा है लेकिन मुझे वि वा है कि पे कमी ान की रिपोर्ट अगले 4–5 महीने के अंदर अंदर आ जायेगी और सरकारी कर्मचारियें के वेतन में जो फर्क होगा, उससे 5–6 करोड रुपये का भार हरियाणा सरकार पर जरूर पड़ेगा। एक बात और हैं भायद इस बात की सराहना अपोजी ान के साथियों ने भी की है। यह हकीकत है इनके जमाने में कांग्रेस सरकार के जमाने में चौधरी भाम ोर सिंह मेरे साथी को इस बात का पता है और वे इस बात से इंकार भी नहीं करेंगे कि इनके जमाने में देहातों से जो थैलियां मिनिस्टर साहबों को भेंट होती थीं, भायद ही वे थैलियां उनको वापिस की हों, लेकिन जनता सरकार ने चौधरी देवी लाल की सरकार ने ये थैलियां वापिस करके एक मिसाल कायम की है। मैं अपनी बात कह सकता हूं कि देहात से चाहे माला की भाक्ल में हार पहनायें चाहे थैली के रूप में दें, वह रुपया उसी वक्त वहीं का वहीं, उस देहात की भलाई के लिये दिया जाता रहा है। (तालियां)

चौधरी सन्त कंवरः इंदिरा गाधंी तो सारे का सारा दिल्ली ले गई।

श्री मूल चन्द जैनः चौधरी देवी लाल इससे एक कदम और आगे गए हैं यह तो हो सकता है कि जितनी रकम देहात

वाले भेंट करें, उसको वही की वहीं वापिस लौटा दें, लेकिन चौधरी साहब इससे एक कदम और आगे गये हैं। जितना रुपया मिनिस्टर साहब को, वी0आई0पी0 को इकट्ठा करके देहात वाले देंगे उतना ही रुपया और डालकर सरकार उस देहाती की डिवैल्पमैंट के लिए वापिस करेगी।

इसके अलावा फूड फार वर्क के लिए सरकार ने 20 हजार टन गेहूं रखा है। अभी अभी फरवरी मार्च के महीने में बी0डी0 ओज0 की मारफत, इरीगे ान डिपार्टमैंट की मारफत देहात की भलाई के लिए काम करने का प्रोग्राम है, गलियों के कच्चे रास्तों पर मिटी डालनी है, कई जगह पर डली भी है। इसके बारे मैं हमारे सामने सुझाव आये हैं कि उन रास्तों को पक्का किया जाए क्योंकि जो मिटी डाली जाएगी वह बारि ा से बह जायेगी, इससे 2 करोड रुपया बेकार जाएगा। सरकार ने इस बात का तुरन्त फैसला किया कि जिन रास्तो ंपर मिटी डाली जाएगी, वे जहां जहां पक्के हो सकते हैं, वहां पक्का किया जाएगा। यह फैसला लिया जा चुका है और इस कार्य के लिए हरियाणा के बजट मैं 2 करोड रुपया और रखा जाएगा ताकि इस प्रोग्राम में कोई कमी न आने पाये। स्पीकर साहब, यह 2 करोड रुपये की रकम बजट में नहीं है, यह सप्लीमैंटरी में आयेगी। स्पीकर साहब, 5 करोड रुपया हरियाणा डिवैल्पमैंट अथौरिटी सरकार से मांग रही है। कहने का मतलब यह है कि 15–16 करोड रुपया तक की ऐसी रकम है जो अगले साल फालतू खर्च करनी होगी।

स्पीकर साहब, इस सिलसिल में एक बात अर्ज कर देता हूं कि बजट दो प्रकार का होता है ..... एक प्लान और दूसरा नान प्लान। स्पीकर साहब, नान प्लान बजट क्या होता है, यह बात मुझे भी मु कल से समझ आई। नान प्लान बजट वह होता है जो खर्चा पुराने जमाने से चला आ रहा है और वह करना ही करना है। प्लान का मतलब यह होता है कि जो आमदनी है, जितने आमदनी के साधन हैं, उन का सारा खर्चा घटा कर जो रुपया बचता है वह प्लान बजट है यानि इस रा ा को प्लान की रकम माना जाता है। हमारी प्लान 227 करोड रुपये की बनी थी। प्लानिंग कमी ान ने हमें यह कहा कि आपके साधन 227 करोड रुपये के नहीं हैं। आपके साधन तो 205 करोड रुपये के हैं आप फालतू प्लान क्यों बना रहे हैं, क्यों 22 करोड कम कर देते ? हमने कहा कि 227 करोड से कम की प्लान हम नहीं बना सकते, मजबूर हैं क्योंकि 205 करोड की प्लान बनाने से प्रदे ा में जो प्रगति ील कार्य हो रहे हैं, वे हमें बंद करने पडेंगे। इसीलिए हमने जनता को कहा कि उसे अपनी कमर कसनी होगी। हमने प्लान ज्यादा बनाया है। प्लानिंग कमी ान ने कहा कि अगर आने 227 करोड की प्लान रखनी है तो आपके 12–15 करोड रुपये के टैक्स लगाने पडेंगे और इसीलिये हमने थोडे से टैक्स लगाये हैं। स्पीकर साहब, मेरे दोस्तों ने जो कुछ कहा, मैं उसकी कदर करता हूं। इन्होंने कहा कि टैक्स लगाते हो, खर्चा क्यों कम नहीं कर देते ? टेक्स में चोरी हो रही है उसको कम करते। स्पीकर साहब, टैक्स की चौरी को रोकने के लिए हम इसी से ान में बिल ला

रहे हैं। माननीय सदस्य चौधरी भाम ेर सिंह को यह ख्याल हो गया था कि भायद हम टाल देंगे, इस से ान में बिल नहीं लाएंगे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह बिल इसी सै ान में ला रहे हैं और फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ के जितने भी बडे बडे कारखाने दार हैं, जिन्होंने अपने दफतर दिल्ली में बना रखे हैं और जो अरबों रुपये का माल हरियाणा में पैदा कर के दिल्ली ट्रांसफर कर देते हैं और बिक्री टैक्स नहीं देते उन पर टैक्स लगाया जाएगा, इस बिल से टैक्स की चोरी बंद होगी, मार्केट फीस की चोरी काफी हद तक रूक जाएगी ऐसा मेरा वि वास है। इसके अलावा और भी सराहनीय कदम उठा रहे हैं। जहां तक खर्चा कम करने का सवाल है, मुझे सदन को बताते हुए खु ी होती है कि सी0एम0 साहब के म ावरे के मुताबिक सरकार ने फैसला कर लिया है कि हरियाणा का कोई मिनिस्टर साहब बड़ी कार इस्तेमाल नहीं करेगा। (तालियां) स्पीकर साहब, चौधरी कंवल सिंह जी ने जिक्र किया था, उनके सुझाव पर मैं उन्हें ट्रिब्यूट पे करता हूं। हमारी पार्टी की जो कमेटी बनी है, उसमें आधे से ज्यादा वजीर हैं, उस कमेटी में उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हम बड़ी कार इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस कमेटी ने यह फैसला किया था कि हरियाणा का गवर्नर और सी0एम0 बे ाक बडी कार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे सी0एम0 साहब ने खास तौर पर कहा कि वे भी छोटी कार इस्तेमाल करेंगे। (व्यवधान) स्पीकर साहब, अब इनको यह चिन्ता हो गई कि ये गाड़िया क्या करेंगे ? ये गाडियां तो जहां से आई थी वही चली जाएंगी। इसके अलावा

हमने एस0टी0डी0 की सहूलियत बंद कर दी। बाहर से जो आदमी आता है, वह कोर्ड नम्बर घुमाता है और झट से टेलीफोन कर लेता है। वह कहीं भी टेलीफोन कर सकता है, यह पता नहीं लगता कि किसने कहां किया है। इसलिए हमने फैसला किया कि एस0टी0डी0 की सहूलियत न किसी मंत्री को होगी, न किसी कर्मचारी को होगी। स्पीकर साहब, मैं सभी दोस्तों की सराहना करता हूं क्योंकि उन्होंने सरकार की कुछ खामियों की तरफ हमारी तवज्जह दिलाई है। मैं स्वामी आदित्यवे ा जी का भी भाुक्रिया अदा करना चाहता हूं हालांकि उनके भाशण से मुझे एक ि ाकायत भी है। गांधी जी मेओ की किताब के बारे में कहा था कि वह ड्रेन इंस्पैक्टर रिपोर्ट है। अपने भाशण में ये अक्सर ऐसा ही करते हैं, लेकिन हर बुराई में से भी कोई न कोई बात निकल ही आती है। इन्होंने कहा कि मिनिस्टरों के ऊपर 49 लाख रुपया खर्च होता है। यह सुनकर मेरे कान खडे हुएं मैंने सोचा कि हम 16 आदमी हैं और अगर यह बात ठीक है तो तीन लाख रुपया फी मिनिस्टर साहब खर्च होग गया। मैंने यह आंकडे मंगवाएं। स्पीकर साहब, जहां तक आंकडों का सवाल है ये तो ठीक है लेकिन इनमें से 1674800 रुपया तो डिसक्रि ानरी ग्रांटस का है। आप जानते हैं कि डिसक्रि ानरी ग्रांटस देने के लिए बाकायदा रूल्ज बने हुए हैं यह सारे का सारा पैसा विकास के कामों में खर्च होता है। यदि मेरे माननीय सदस्य यह जानना चाहते हों कि मैंने अपनी डिसक्रि ानरी ग्रांट को कैसे इस्तेमाल किया है तो मैं इसकी डिटेल दे सकता हूं (विघ्न) तो पौने सतरह लाख रुपया तो यह

हुआ। फिर अध्यक्ष महोदय, साढे सताईस लाख रुपया हमारी कारो, दफतर और रेजिडेंस आदि की मेन्टेनैंस के ऊपर खर्च होता है। इसके लिए, आपको जानकर खु ी होगी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि अब मिनिस्टर साहेबान बडे घरों में नहीं रहेंगे। (प्र ांसा) वे या तो छोटे घरों में रहेंगे या एम0एल0ए0 फ्लैटस में रहेंगे। (विघ्न) चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि सभी एम0एल0ए0 फ्लैटस में रहेंगे। (विघ्न) इसके अलावा स्पीकर साहब, बडी कारों के ऊपर जो खर्चा था वह ज्यादा था। मेरा ख्याल है कि अब छोटी कारें होने पर यह खर्चा भी काफी कम हो जाएगा। इसके बाद हम कोि ा ा करेंगे कि मिनिस्टर साहबों के दौरे नियमित रूप से हों। (विघ्न) सीलिंग तो लगी हुइ है लेकिन हम कोि ा ा करकंगे कि वे ठीक ढंग से हों।

श्री भाम ोर सिंहः एयर कंडी ानर्ज भी बंद होने चाहिए। दफतरों में भी और घरों में भी (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, वेस्टफल ऐक्सपैंडिचर जिसे कहा जाता है उसके संबंध में जब मंत्री महोदय अपने ऊपर पाबंदी लगा लेंगे तो मुझे वि वास है कि विधायगण भी और हमारे सरकारी कर्मचारी भी ऐसा करने की बात सोचेंगे। मुझे वि वास है कि ऐसा करने से खर्चे में काफी कमी आएगी। (विघ्न)

स्पीकर साहब, एक बात मैं भूल गया। वह भी मैं अर्ज कर देता हूं। हमारे जिने कारपोरे ांज हैं, इनके बारे में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक दो को छोड कर सभी में नुक्सान हो रहा है। हमारे कांग्रेसी भाईयों ने भी यह आरोप लगाया कि इनमें घाटा हो रहा है। घाटे की बता तो ठीक है लेकिन ये अपने गरेबान में भी मुंह डाल कर देखें कि आंध्र प्रदे ा में क्या हो रहा है ? और कर्नाटक में क्या हो रहा है ? स्पीकर साहब, जो फैक्ट है, जो असलियत है उसको स्वीकार करने वाले का भी भला होता है और सारे समाज का भी भला होता है। चौधरी भाम ेर सिंह जी जरा गहराई से देखिए। पिछले साल भाराब के ठेके देने में हमारे से गलती हुई लेकिन हमने वह स्वीकार कीं आप भी गलतियां स्वीकार करें। हमने तो उन नियमों को सुधारने के लिए पहले से ही कदम उठाए हैं इसमें कुछ समय तो लगेगा लेकिन इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान हैं हमने पब्लिक अंडर टैंकिंग्ज कमेटी बनाई हुई है। उसकी जो सिफारि ा आएगी उन पर अमल किया जायेगा। इसके अलावा फाईनैंस डिपार्टमैंट में भी एक अलाहिदा सैल बनाया गया है। वह भी इनके कार्यकलाप को देखेगा।

स्पीकर साहब, अब मैं आखिरी बात पर आता हूं। हमारे दोस्तों ने टैक्सों में रिलैक्से ान देने के बारे में कुछ सुझाव दिए। यहां कहा गया कि हमारे प्रदे ा में कपास की कीमत कम हो गई। गन्ना सस्ता हो गया। आलू भी सस्ता बिका है फ्लड में किसान का

बहुत नुकसान हुआ है और अब ओलों से नुकसान हो गया। ऐसी भाक्ल में आबियाना नहीं बढना चाहिए। इस सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं (प्र ांसा) इसके अलावा जो भूमि कर हमने सवा छः एकड से ज्यादा भूमि के मालिकों पर लगाया था वह मैं भी समझता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब भी सहमत हैं कि इसमें कुछ रिलैक्से ान दी जानी चाहिए क्योंकि किसान की आर्थिक दृश्टि से यह ठीक नहीं है। इसके बारे में नया सुझाव यह है कि 12 एकड तक किसी फार्म में यह नहीं बढेगा। 12 से 15 एकड तक दस परसैंट बढेगा और 15 एकड से ज्यादा भूमि पर चाहे वह कितने ही हो 15 फीसदी बढेगा। (विघ्न) स्टैंडर्ड एकड़ वाली बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसमें गडबड होगी। स्पीकर साहब, इसमें एक रिसायत और है यह टैक्स 12 एकड भूमि निकाल कर लगेगा। (प्र ांसा) इससे किसाने के ऊपर बहुत ही कम बर्डन रह जाएगा।

स्पीकर साहब, हलवाईयों के बारे में भी मेरे दोस्तों ने भिन्न बातें कहीं। कुछ ने कहा कि हलवाईयों के ऊपर बिलकुल टैक्स न लगाया जाए। कुछ ने कहा कि यदि टैक्स लगाओ तो मुख्तलिफ ग्रेडज बना दिए जाएं जैसे सिविल सप्लाई डिपार्टमैंट से जब ये खांड लिया करते थे तो तीन ग्रेड बने हुए थे। उसी हिसाब से ग्रेड बनाकर लम्प सम में टैक्स लगा दिया जाए। स्पीकर साहब, एक अखबार वाले ने भी कहा है औरा मेरा भी यह अनुभव है कि यह एक ऐसा प्रोफै ान है जिसमें बाकी प्रोफै ांज के मुकाबले में काफी मुनाफा रहता है। आजकल तो आम कहा जाता है कि चीनी

तो सस्ती हो गई लेकिन मिठाई आदि का रेट वही है जो पहले था। इसलिये इनके ऊपर जितना टैक्स लगा है उससे इन पर कोई ज्यादा बोझ नहीं पडेगा लेकिन रिटर्न के चक्कर से बचाने के लिए, सेल्ज टैक्स आफिस के चक्कर से बचाने के लिए उनके ग्रेड बना दिए जाएं। स्पीकर साहब, सैल्ज टैक्स एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि यह किसी पर्टिकुलर ट्रेड को रिटर्न के चक्कर से बचाने के लिये उससे लम्प सम में टैक्स ले सकती है। तो इस तरह से हलवाइयों के ऊपर टेक्स लगेगा। इसके अलावा एक बात और होगी।

श्री मांगेराम गुप्ताः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। हलवाइयों के बारे में जो बात इन्होंने कही है कि लम्प सम टैक्स वसूल करेंगे। वे इस बात को कलियर करें कि किस प्रकार से वसूल करेंगे।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, एक टैक्स और रह गया जिसके बारे में भी सुझाव आये थें वह पेसेंजर फेयर था। यह 12.5 परसैंट बढा है। कहा गया कि यह बहुत ज्यादा है। कई माननीय सदस्यों का इस पर एतराज था कि इतना ज्यादा नहीं बढना चाहिए। वैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल सारी चीजें महंगी हो गई हैं। हमने कंडक्टरर के, ड्राईवर के अलाउंस भी बढायें हैं। दूसरी तरफ पैट्रोल और डीजल भी काफी महंगा हो

गया हैं मोटरों के पुर्जे भी काफी महंगा हो गये हैं। इन सारी बातों के होते हुए भी हमने साढे बारह परसैंट से 10 परसैंट कर दिया है। अब हमने जो टैक्सिज कम किये हैं उनसे जनता को काफी राहत मिलेगी। आबियाने का चालीस लाख रुपये का बजट में सुझाव था वह बिल्कुल हटा दिया है। भूमिकर का भी 90 लाख रुपया कम हो गया है। अब यह तीस लाख होगा। इसी प्रकार पैसेंजर टैक्स से तीन करोड चालीस लाख रुपये की आमदनी होनी थी लेकिन उसमें भी 87 लाख रुपया कम हो जायेगा।

श्री सभापतिः आप किराये के बारे में बताइये।

श्री मूल चन्द जैनः मैं जो भी कुछ कह रहा हूं। वह आपके सामने है। बजट में बसों के किराये का साढे बारह परसैंट बढाने का सुझाव था लेकिन सदस्यगण के एतराज को देखते हुए दस परसैंट किया है इससे अधिक कम करने की पोजी ान में हम नहीं थे। बजट की पोजी ान को देखते हुए इतना ही कन्सै ान दिया जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता।

चौधरी पीज चन्दः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आपके जरिये चीफ मिनिस्टर साहब से और फाइनैंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हम इस दस परसैंट को भी ज्यादा समझते हैं। इसलिए पैसेंजर टैकस यदि बिलकुल खत्क कर दिया जाये तो बहुत अच्छी बात होगीं इसमें तरमीम आनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, बाकी जो और टैक्सिज हैं उनके बारे में कोई खास नुक्ताचीनी नहीं हुई है। (विघ्न) राव साहब कह रहे हैं कि वै हिबे या रहन केरने पर स्टाम्प डयूटी खत्म होनी चाहिए लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 1967 में जब राव साहब चीफ मिनिस्टर साहब होते थे यह रेट 12.5 परसैंट ही हुआ करता था।

राव बीरेन्द्र सिंहः तब भी आपने ही लगाया था। मेरे वक्त में भी आप ही फाईनैंस मिनिस्टर साहब थे।

श्री मूल चन्द जैनः अब फिर मेरी किस्मत में दस से साढे बारह परसैंट करना आ गया। कुछ भाईयों का यह गलतफहमी है कि लैंड मार्गेज बैंक्स आदि से जब किसान लोग कर्जा लेते हैं और उनको अपनी जमीन गिरवी रखनी पडती है तो उस पर की स्टाम्प डयूटी लगती है। यह गलत बात है उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मैंने यह बात पार्टी मिटिंग में भी एक्सप्लेन की थी और अब हाउस में भी बता दिया है कि उन पर किसी प्रकार का स्टाम्प आदि टैक्स नहीं लगता है। उन लोगों पर तो टैक्स बढाने का सवाल ही नहीं है लेकिन जो अपनी जमीन बेचेगा प्लाट बेचेगा या कोई और जायदाद बेचेगा उस पर यह टैक्स लगेगा। (विघ्न) मेरे साथी यह स्वीकार करेंगे कि यह टैक्स गरीब लोगों पर नहीं है। गरीब पर उस हद तक तो है अगर वह अपनी जायदाद बेचता है या लेता है लेकिन आम तौर पर जो बडे

लोग हैं पैसे वाले हैं या जायदाद वाले हैं, वही खरीदो–फरोख्त करते हैं और उन्हीं पर यह टैक्स लगेगा।

इसके अलावा श्री मांगेराम गुप्ता जी ने धागे की बात कही। मैं मानता हूं कि पहले धागे पर एक परसैंट टैक्स था। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि पंजाब ने इसे एक परसैंट से बढा कर दो परसैंट कर दिया है। यू0पी0 ने भी दो परसैंट कर दिया। केवल दिल्ली प्रदे ा ऐसा है जिसमें एक परसैंट है। उन्होंने कहा कि दो परसैंट कर देने से इस ट्रैड को नुक्सान होगा। इस पर हरियाणा सरकार विचार करेगी और उचित समझेगी तो इसे तबदील करेगी।

स्पीकर साहब, मैंने काफी समय हाउस का लिया। मैं सभी माननीय सदस्यों का भ्ुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ध्यानपूवर्क सुना। आखिर में यह कह कर अपना स्थान लेता हूं कि जनता पार्टी के सामने जो मंजिल है उसकी तरफ यह धीरे धीरे बढ रही है। जनता पार्टी की सरकार आने के प चात हरिजन भाइयों को चौपालों के लिये पैसा दिया गया। इसी प्रकार गांवों में और भी काम किये जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने उस लक्ष्य पर पहुंचे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करेंगे।

वाक आउट

अपोजी ान बैंचिजः पैसेन्जर टैक्स वापिस लो। (विघ्न) आप यह वापिस नहीं लेते तो हम वाक आउट करते हैं।

(इससमय सर्वश्री राव बीरेन्द्र सिंह, भाम ोर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, नारायण सिंह, मांगे राम गुप्ता, बीरेन्द्र सिंह और इन्द्रजीत सिंह सदन से वाक आउट कर गये।)

श्री अध्यक्षः अब सदन कल दिनांक 23 मार्च 1979 सुबह साढ़े नौ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

***17.57 hours**

(The Sabha then *adjouned till 9.30 a.m. on Friday, the 23rd March, 1979.)